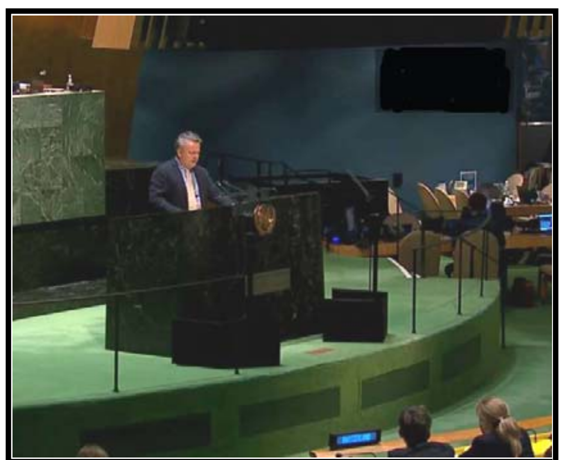
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार निकाय (UNHRC) से रूस को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मांग से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया। वहीं 24 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 114 दिनांक: 08-04-2022 शुक्रवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

नई दिल्ली में गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बज़ट सत्र के बाद सम्बोधन देते हुए

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् से रूस निलंबित

संयुक्त राष्ट्र (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् से रूस को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से बाहर करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। 93 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। वहीं, 24 सदस्यों ने इसका विरोध किया और 58 सदस्य मतदान से दूर रहे। भारत ने भी मतदान से दूरी बनाई है। मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश हैं। जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। परिषद से रूस के निलंबन का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय का आपातकालीन विशेष सत्र गुरुवार को सुबह 10 बजे फिर से शुरू हुआ। इस दौरान रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई। मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं, जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। महासभा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से 'मानवाधिकारों के घोर और व्यवस्थित उल्लंघन करने वाले परिषद के सदस्य की परिषद में सदस्यता निलंबित कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रोमानिया में संवाददाताओं से कहा था कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदारों के साथ करीबी समन्वय कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस का निलंबन चाहता है। इससे पहले भी मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बूचा नरसंहार के मामले पर रूस की जमकर निंदा हुई थी और हर तरफ से रूस की जवाबदेही तय करने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग उठी थी। महासभा वोटिंग करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करने वाले किसी देश की परिषद सदस्यता निलंबित कर सकती है।

आंध्रप्रदेश की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करेंगे

अमरावती (ईएमएस)। आंध्रप्रदेश मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री जगन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करेंगे। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पहले चरण में 24 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे। कैबिनेट में एकमात्र सीएम जगन रेड्डी ही बचे हैं, जिन्हें इस्तीफा सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर अपने मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी दी है।

मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाना तय था, क्योंकि सीएम ने कहा था कि उनका आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद वे अपनी टीम बदल देंगे। यह बदलाव दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टालना पड़ा।

इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक - पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बाद अब नए सिरे से चुनाव कराने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष की ओर से विवादित व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के अहम मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई फिर से शुरू की। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति एजाज़-उल अहसन, न्यायमूर्ति मज़हर आलम खान मियांखाइल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाइल शामिल हैं। पीठ ने सुबह मामले की सुनवाई शुरू की।

अखबार 'डॉन' की खबर के मुताबिक, बंदियाल ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के वकील सीनेटर अली ज़फर से पूछा कि यदि सब कुछ संविधान के मुताबिक चल रहा है तो मुल्क में संवैधानिक संकट कहां है? ज़फर की ओर से अपनी दलीलें पूरी करने के दौरान बंदियाल की यह टिप्पणी आई। एक बार तो, बंदियाल ने वकील से पूछा कि वह यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि देश में संवैधानिक संकट है या नहीं।प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''अगर सब कुछ संविधान के मुताबिक हो रहा है तो संकट कहां है?'' सुनवाई के दौरान मियांखाइल ने जफर से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जन प्रतिनिधि हैं ? तो वकील ने हां में जवाब दिया।मियांखाइल ने तब पूछा कि क्या संसद में संविधान का उल्लंघन होने पर प्रधानमंत्री को बचाया जाएगा?इस पर ज़फर ने जवाब दिया कि संविधान की रक्षा उसमें बताए गए नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हर अनुच्छेद को ध्यान में रखना होगा।बंदियाल ने फिर पूछा कि तब क्या होगा जब सिर्फ एक सदस्य के साथ नहीं, बल्कि पूरी असेंबली के साथ अन्याय हो।

इससे पहले न्यायालय ने बुधवार को कथित ''विदेशी साजिश'' के बारे में और जानकारी के लिये सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की बैठक के विवरण मांगे थे और इस बात पर अपना फैसला टाल दिया कि क्या इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय संसद को भंग करा संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।

संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, कुल 11 विधेयक पारित

- इस सत्र लोकसभा में 129 प्रतिशत और राज्यसभा में 98 प्रतिशत कामकाज हुआ

- कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के चलते सत्र में कटौती की गईः मंत्री प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद का बजट सत्र, 2022 जो 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां बजट सत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि पूरे बजट सत्र, 2022 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की 27 बैठकें हुईं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस सत्र में मूल रूप से 8 अप्रैल, 2022 तक बैठकें होनी थीं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण उसमें कटौती की गई। इस प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी मौजूद थे।

संसद का बजट सत्र, 2022 जो सोमवार 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इससे पहले सोमवार, 14 मार्च, 2022 को पुनः एकत्रित होने के लिए शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को राज्यसभा और लोकसभा को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया गया था, ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें। बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। सत्र के पहले भाग के दौरान, कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा पब्लिक गैलरी, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा पब्लिक गैलरी का उपयोग किया।

सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर

बरेली (ईएमएस)। बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री शहजिल इस्लाम के कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सपा विधायक इस्लाम के बरेली-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर परसाखेड़ा स्थित पेट्रोल पंप को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

उन्होंने बताया क यह पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया है।

यूरोपीय संघ में पड़ी दरार, हंगरी करेगा रूबल में भुगतान

बुडापेस्ट । हंगरी ने यूरोपीय यूनियन (ईयू) की एकजुटता को धता बताते हुए रूस को गैस और तेल की खरीद के लिए रूबल में भुगतान करने का फैसला किया है। इससे पहले वह रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाने से भी इन्कार कर चुका है। इस बीच हंगरी ने परमाणु संयंत्र चलाने के लिए आवश्यक ईंधन रूस से हवाई मार्ग से मंगवाया है। आपको पता होगा कि यूक्रेन का पड़ोसी हंगरी नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) का भी सदस्य है।

ईयू ने कहा है कि सदस्य देश रूस के साथ तेल और गैस खरीद के अपने मूल समझौते पर कायम रहें। इस समझौते के अनुसार यूरोपीय देशों को तेल और गैस खरीद के लिए यूरो और अमेरिकी डालर में रूस को भुगतान करना है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते एक आदेश पर हस्ताक्षर कर तेल, गैस और कोयले का मूल्य अपनी मुद्रा रूबल में लेने के लिए रूस की कंपनियों को कहा था।

फिलहाल अग्रिम भुगतान से यूरोपीय देशों को तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस रूबल में भुगतान के लिए कहता है तो वह रूसी मुद्रा में तेल और गैस मूल्य के भुगतान के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हंगरी और रूस द्विपक्षीय समझौते के तहत तेल और गैस की खरीद-बिक्री करते हैं, इसमें ईयू की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इस बाबत ईयू के दिशानिर्देशों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हंगरी के हित रूस से तेल और गैस लेना जरूरी है, इसलिए लेते रहेंगे। रूस के सहयोग से हंगरी में स्थापित परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन पहले यूक्रेन होते हुए रेलमार्ग से रूस से हंगरी आता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते यह हवाई मार्ग से मंगवाया गया है। जबकि ब्रसेल्स में ईयू के सांसदों ने गुरुवार को मतदान के जरिये रूस से कोयला आयात पर पूर्ण प्रतिबंध पर मुहर लगा दी लेकिन तेल और गैस पर कोई बाध्यकारी फैसला नहीं हो पाया है। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ में मतभेद देखने को मिल रहा है। ऐसे में हंगरी ने घोषणा कर कहा है कि वह गैस की कीमत का भुगतान रूबल में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

केरल कांग्रेस में बड़ी बगावत केवी थॉमस ने किया हाईकमान के आदेश को तोड़ने का ऐलान

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि पार्टी के लिए यह वक्त चुनौतीपूर्ण है और उससे निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कलह का सामना कर रही कांग्रेस अब केरल में भी गुटबाजी और बगावत का शिकार होती दिख रही है। केरल के सीनियर नेता केवी थॉमस ने सीपीएम की ओर से आयोजित सेमिनार में शामिल होने का फैसला लिया है, जबकि हाईकमान ने इस पर रोक लगाई थी। कांग्रेस नेतृत्व के सख्त दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए केवी थॉमस ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह सत्तारूढ़ माकपा द्वारा पार्टी कांग्रेस के तौर पर कन्नूर में आयोजित किए जा रहे सेमिनार में भाग लेंगे। बहरहाल थॉमस ने यह स्पष्ट किया कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, 'मैं माकपा के राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने जा रहा हूं। मुद्दा मेरे लिए ज्यादा अहम है न कि राजनीति।' थॉमस के अलावा माकपा ने उत्तरी कन्नूर जिले में हो रही पार्टी कांग्रेस के तौर पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनार में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी आमंत्रित किया है। हालांकि जब थरूर ने इसमें भाग लेने की अनुमति मांगी तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति प्रमुख सोनिया गांधी ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया।

मोदी सरकार के खिलाफ फिर आंदोलन करने को तैयार किसानः टिकैत

मुजफ्फरनगर (ईएमएस)। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देकर फिर से आंदोलन शुरू करने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि सरकार चुनाव से पहले किसानों से किये वादे भूल गई है। उन्होंने किसानों से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। टिकैत का कहना है, कि केंद्र सरकार ने पिछले साल किसानों से किए वादों को अभी तक नहीं निभाया। टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सरकार ने कई और भी वादे किए थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आंदोलन की तैयारी पूरी है।

टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार किसानों से किए वादे भूल गई है। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द वादे पूरे नहीं हुए, तब किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं। उधर किसान यूनियन के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने भी किसानों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि एक बार फिर से तैयार हो जाएं लंबा संघर्ष करना होगा।

कश्मीरी पंडितों पर अन्याय किया और आज फिल्म टैक्स फ्री की बात कर रहे केजरीवाल का भाजपा पर हमला

जम्मू (ईएमएस)। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश में भाजपा समर्थित सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे में साफ हो जाता है कि कश्मीरी पंडितों पर अन्याय के लिए भाजपा जिम्मेदार है और इस घटना के 32 साल बाद भाजपा इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि आज ये लोग द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात करते हैं लेकिन उस वक्त जो हुआ था उसके लिए भाजपा सरकार ही जिम्मेदार थी, उस घटना के बाद 32 सालों में 15 साल भाजपा ने केंद्र पर राज किया है लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साफ जाहिर होता है कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। केजरीवाल ने कहा कि उस वक्त देश में भाजपा समर्थित सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल भाजपा से ताल्लुक रखते थे। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने गठबंधन में सरकार चलाई है। अगर भाजपा को सच में कश्मीरी पंडितों की चिंता थी तो इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उन लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि जब देश के लिए उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था तो उस वक्त वो 15 दिनों तक भूखे रहे। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अगर ज्यादा दिन भूखा रहा तो नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं मधुमेह रोगी हूं। लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। लोगों के लिए हमेशा लड़ता हूं और आगे भी लड़ूंगा।

दबाव के बीच भारत-अमेरिका टू प्लस टू वार्ता होना तय, दो दिन के लिए अमेरिका जाएंगे राजनाथ सिंह और एस जयशंकर

नई दिल्ली। पिछले एक हफ्ते के भीतर जो बाइडन प्रशासन के कम से कम चार वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग मौकों पर भारत को यह चेतावनी दी है कि उसने रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच होने वाली टू प्लस टू वार्ता का एजेंडा क्या होगा यह कोई अनुमान लगाने का मुद्दा नहीं रहा। गुरुवार को भारत और अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि इनके विदेश और रक्षा मंत्रियों की टू प्लस टू वार्ता 11 अप्रैल, 2022 को होगी। वार्ता में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन जाएंगे। अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लायड आस्टिन करेंगे।

जहां तक अमेरिकी दबाव का सवाल है तो भारत ने गत दो हफ्तों के दौरान साफ तौर पर दिखाया है कि वह अपने हितों के मुताबिक ही काम करेगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब यह पूछा गया तो उनका जवाब बहुत सांकेतिक था। बागची ने कहा कि, रूस के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते काफी व्यवस्थित रहे हैं लेकिन मौजूदा परिवेश में उसे स्थिर बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस के साथ रुबल-रुपये में कारोबार करने के बारे में अंतिम फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। अमेरिका की तरफ से रूस से ज्यादा इंधन नहीं खरीदने के सवाल पर बागची ने विदेश मंत्री एस.जयशंकर की तरफ से बुधवार को संसद में दिए गए बयान का उद्धरण दिया कि यूरोपीय देश अभी तक रूस से इनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। जहां तक रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का सवाल है तो इसको लेकर स्थिति काफी अस्पष्ट है।

भारत और अमेरिका के बीच यह चौथी टू प्लस टू वार्ता होगी। बागची ने कहा कि आगामी बैठक दोनों देशों को विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग से जुड़े तमाम मुद्दों पर विमर्श करने का मौका देगा। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं और इस बैठक में क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विमर्श होगा। अमेरिका ने इस साल की बैठक को इस लिहाज से महत्वपूर्ण बताया कि इस वर्ष दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों के स्थापित होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और अमेरिका एक मजबूत व महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार के तौर पर भी स्थापित हो रहे हैं और आगामी बैठक में इस संदर्भ में विमर्श का मौका होगा। भारत की तरफ से जारी संक्षिप्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र नहीं है लेकिन अमेरिकी बयान में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला व सभी के लिए समान अवसर वाला क्षेत्र बनाने, जो भौगोलिक अखंडता व संप्रभुता को बनाये रखने में भरोसा करे और मानवाधिकार की सुरक्षा करे, पर भी बात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री चौथी भारत-अमेरिका मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह वार्ता 11 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी। इस दौरान विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष सचिव एंटनी ब्लिंकेन से भी अलग से मुलाकात करेंगे।

जल शक्ति मंत्री 8 अप्रैल को जयपुर में 11 राज्यों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। केन्द्रीय जल मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत 8 अप्रैल, 2022 को जयपुर में 8 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत हासिल प्रगति और आगे बढ़ने की कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय सम्मेलन में 8 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश यानी गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली भाग ले रहे हैं। बैठक में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के 10 मंत्री व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

सम्मेलन के माध्यम से, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य हासिल की गई जानकारी को साझा करना, सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संभावित समाधान खोजना है। दोनों प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक राज्य/ संघ शासित प्रदेश द्वारा की गई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि विभिन्न नियोजित गतिविधियों में तेजी लाने के साथ-साथ आगे का रास्ता निकाला जा सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव, अपर सचिव और मिशन निदेशक (जेजेएम/ एसबीएम-ग्रामीण) भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

भारत और नीदरलैंड बल्कि भारत व यूरोप के बीच सेतु के रूप में काम करता है : राष्ट्रपति कोविंद

नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय समुदाय भारत-नीदरलैंड के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और न केवल भारत व नीदरलैंड बल्कि भारत और यूरोप के बीच एक सेतु का काम करता है। वह नीदरलैंड में भारत की राजदूत रीनत संधू की ओर से 6 अप्रैल एम्स्टर्डम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के मित्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यूरोप के मुख्य भूभाग नीदरलैंड में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा भारतीय मूल का प्रवासी है, जिसमें हिन्दुस्तानी-सूरीनामी समुदाय के दो लाख (200,000) से अधिक सदस्य हैं और 60,000 से अधिक भारतीय पेशेवर व छात्र रहते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि नीदरलैंड में भारतीय पेशेवरों ने बहुत अच्छा काम किया है। उद्यमियों, डॉक्टरों, बैंकरों और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में वे बड़े पैमाने पर डच समाज और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैश्विक समुदाय के लिए अत्यधिक मूल्यवान साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धियों और सफलता पर भारत को गर्व है। कोई एक भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकता है, लेकिन किसी भारतीय से भारत को नहीं ले जाया जा सकता है। पिछले सैकड़ों वर्षों में कई भारतीयों ने विदेश यात्राएं की हैं जबकि भारत हमेशा उनके दिलों में धड़कता रहा है। वे दुनिया के जिस भी हिस्से में बसे उन्होंने भारतीय सभ्यता के मूल्यों को गर्व के साथ जीवित रखा। भारतीय मूल के लोग जहां भी बसे उन्होंने उस जगह को अपने घर के रूप में मान लिया और पूरी तरह से उससे जुड़ गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों ने सामग्री और मौद्रिक दान के माध्यम से अपना सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सभी सामग्री और मौद्रिक दान का सदुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमें याद आता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी हमारा विस्तारित परिवार है जो हमें अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।

कार्टून कोना

मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मंहगाई मुक्त भारत अभियान''

- तेल के दाम बेलगाम, अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते कम होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और गैस की दरों में असहनीय बढ़ोत्तरी : चौ. अनिल कुमार

-मोदी सरकार की हठधर्मिता व तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर मंहगाई के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे : शक्तिसिन्ह गोहिल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार की अध्यक्षता तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के आव्हान पर मंहगाई मुक्त भारत अभियान के तहत भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर धरना दिया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई से देशवासियों को राहत दिलाने के लिए भाजपा की मोदी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार के तेल के खेल को बंद करवाने के लिए एकजुट हुआ हैं।

चौ. अनिल कुमार ने कहा कि मोदी केजरीवाल के पिछले 8 वर्षो के तानाशाही शासन में जनता के हाथां सिर्फ रिकार्डतोड़ महंगाई और बेरोजगारी आई है। मोदी सरकार प्रतिदिन 80 पैसे की बढ़ोत्तरी करके एक तरफ देश की जनता पर आर्थिक बौझ डाल रहे है तो दूसरी ओर तेल कम्पनियों को फायदा पहुॅचाकर केन्द्रीय राजस्व में एक्साईज़ डयूटी की बढ़ोतरी करके अतिरिक्त कमाई कर रहे है। उन्हांने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी-पीएनजी के दाम भी प्रतिदिन बढ़ाकर लोगों की चौतरफा कमर तोड़ रही है। पिछले एक महीने में 9 बार सीएनजी के दाम 12.10 रुपये बढ़ाने के बाद सीएनजी प्रतिकिलो 69.11 रुपये में मिल रही है, जबकि आज पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर होने का सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। चौ. अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार प्रतिदिन किश्तां में लोगां पर महंगाई का प्रहार कर रही है।

चौ. अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा की केन्द्र में मोदी के नेतृत्व में झूठ, लालच और लूट की सरकार चलाने का लक्ष्य है, जिसके तहत उन्होंने पूरे देश बेचने की रुपरेखा तैयार कर रखी है जिसके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है और मोदी के पूंजीपति मित्र विश्व में टॉप टेन की गिनती में आ रहे है। उन्होंने कहा कि मोदी मंत्रीमंडल तेल की कीमतां में बढ़ोत्तरी यूक्रेन रशिया युद्ध की दुहाई दे रहे है परंतु चुनावों से पहले दिसम्बर में बारम्बार तेल कीमतों में बढ़ोत्तरी किन कारणों से हुई यह नही बताते। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा गरीबों के हकों की लड़ाई में सहायक बनने की जरुरत है।

चौ. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में महंगाई के लिए केजरीवाल सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है क्योंकि जब तेल कीमतों के दिल्ली सरकार द्वारा लागू वेट भी बढ़ता है। केजरीवाल झूठी और खोखली घोषणाऐं करके दिल्लीवालों को महंगाई से राहत देने की जगह उन्हें गुमराह कर रहे है। उन्हांने कहा कि दिल्ली में महंगाई इतनी बढ़ गई कि गर्मियों में रोजमर्रा की जरुरत निंबू 300 रुपये किलो पहुच गया है, जबकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है। राजधानी में केजरीवाल के शासन महंगाई इस कदर प्रभावित कर रही है गरीब आदमी तो वक्त रोटी नही जुटा पा रहा है।

श्री शक्तिसिन्ह गोहिल ने कहा कि आज नवरात्रि, रमजान उपवासों के पर्व पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी व श्री राहुल गांधी जी के आव्हान पर मंहगाई मुक्त भारत अभियान की लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से साफ हो गया है कि भाजपा की मोदी सरकार की हठधर्मिता व तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है और बड़ी से बड़ी लड़ाई उसी प्रकार जीत सकते है जिस प्रकार हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता के हितों को कभी भी नजरअंदाज नही किया गया तथा पेट्रोल 70 रुपये, डीजल 59 रुपये, रसोई गैस 410 रुपये तथा महंगाई पर हमेशा नियंत्रण रखा गया।

जन हितैषी

सतर्कता अब भी जरूरी

कोरोना जैसी भयानक महामारी को लेकर अपने देश में इसकी निगरानी करने वाली सबसे बड़ी संस्था ने राहत भरी घोषणा की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुख्य महामारी विशेषज्ञ ने भारत को अब कोरोना महामारी से मुक्त घोषित कर दिया है। अब भारत में कोरोना एंडेमिक कैटेगरी में पहुंच गया है। यानी यह वायरस तो हमारे आपके बीच मौजूद रहेगा, लेकिन अलग-अलग बदले हुए स्वरूप में होगा। जो अब अपने पुराने महामारी जैसे हालात में नहीं पहुंच सकेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जनजीवन और सामान्य होता जाएगा। हालांकि अब पूरे देश को अगले कई सालों तक कोरोना वायरस के बदले हुए तमाम रूपों से दो चार होना ही पड़ेगा।

यह दावा आईसीएमआर के मुख्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने किया है। वे कहते हैं कि देश में कोविड जैसी खतरनाक महामारी का अब अंत हो चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में फिलहाल अब किसी भी तरीके का कोरोना वायरस का बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। जिस तरीके के मामले और आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अब इस बीमारी को एंडेमिक कैटेगरी में रखा जा रहा है। यानी अब यह बीमारी पूरे देश में सभी राज्यों के सभी शहरों, गांवों, तहसीलों और कस्बों में अपना कहर बरपाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वह कहते हैं कि संभव है किसी राज्य में किसी शहर में मामले जरूर बढ़ें, लेकिन इसका प्रकोप एक साथ पूरे देश में अब देखने को नहीं मिलेगा। आईसीएमआर के पास मौजूद डाटा, तो इसी बात की तस्दीक कर रहा है। इसी के आधार पर अब कोरोना जैसी महामारी को एंडेमिक निपाह जैसी बीमारी के बराबर रखा गया है। बहुत से राज्यों ने मास्क लगाने की छूट दे दी है। वह कहते हैं कि आज के हालात के मुताबिक ऐसी छूट जरूर दी गई है, लेकिन लोगों को मास्क लगाना चाहिए। ऐसी कोई सूरत बनती इसलिए भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन कुछ शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही थी, वहां उनकी तादाद फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना को तो हारना ही है, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि उस पर जल्द काबू पाया जाए। यह कोशिश केवल केंद्र और राज्यों के साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को ही नहीं करनी, बल्कि आम जनता को भी करनी है। सब जान रहे हैं कि कोरोना से बचाव का उपाय सेहत के प्रति सतर्कता, एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखना और मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही देखने को मिल रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मास्क का इस्तेमाल करने से या तो बचा जा रहा या फिर उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति सार्वजनिक स्थलों पर एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखने के मामले में भी देखने को मिल रही है। यह जान-बूझकर खतरे की चपेट में आने वाला काम है। निःसंदेह कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि आवश्यक सावधानी का परिचय देने से इंकार किया जाए। चूंकि ऐसा किया जा रहा है, इसलिए कोरोना काबू में आता नहीं दिखता। समझना कठिन है कि लोगों को मास्क का सही इस्तेमाल करने में क्या परेशानी है? यह संतोष की बात अवश्य है कि कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं और मृत्यु दर में गिरावट जारी है, लेकिन आखिर इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है कि करीब 70 हजार लोग काल के गाल में समा गए हैं और इनमें वे भी हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी? अच्छा हो कि लोग यह समझें कि यदि उनकी ओर से अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशों पर पानी ही फिरेगा। कोरोना विषाणु के संक्रमण की कोई निश्चित प्रकृति नहीं रही है, इसलिए समय के साथ उसकी चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। इसलिए उन्हें भी टीकाकरण के जरिए सुरक्षित बनाया जाए। इसके अलावा, सरकार ने उन बुजुर्गों के लिए टीके की एहतियाती खुराक देने की घोषणा की है, जिन्होंने पहले दो खुराक ले ली है। माना जा रहा है कि चूंकि कोविड-19 से ग्रसित होने के लिहाज से बुजुर्ग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए टीके की दोनों खुराक के बाद तीसरी और एहतियाती खुराक लेने से कोरोना विषाणु के संक्रमण के खतरे से बचाव में ज्यादा मदद मिलेगी! हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना विषाणु के संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी आई है। मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक सीमा तक सुरक्षित स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए घोषित सख्त नियम-कायदों और पाबंदियों में काफी राहत दी गई है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना और उसके अलग-अलग बहुरूप के संक्रमण की जो प्रकृति रही है, उसके मुताबिक अगर इससे बचाव और सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई तो उसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं।

नौकरशाही की आशंका

- मुतखोरी से 'लंका काण्ड' की पुनरावृत्ति....?

लगता है इस कलियुग में भारत में 'त्रैतायुग' की पुनरावृत्ति होने वाली है, त्रैतायुग में भारत में रामराज था और लंका में 'रावणराज'। भारत में खुशहाली समृद्धि थी तो लंका में अत्याचार व शोषण। तब राम ने अपनी 'लीला' दिखाकर रावणराज का अंत किया था। आज भी भारत में खुशहाली है और लंका में बदहाली, वहां की जनता सरकार की मुतखोरी की इतनी आदी हो गई कि उस पर 'ब्रेक' लगने पर हिंसक आंदोलन पर उतर आई, मंहगाई वहां चरम पर पहुंच गई, फलस्वरूप भूखे लोग आंदोलन पर उतारू हो गए, हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता की कौशिश की किंतु वह 'ऊँट के मुंह जीरा' साबित हुई और फलस्वरूप वहां अशांति व विद्रोह नियंत्रण से बाहर हो गए और अंततः वहां की सरकार को सिंहासन त्यागना पड़ा।

यह तो हुई हमारे पड़ौसी देश में घटे घटनाक्रम की बात। अब यदि हम हमारे देश की सरकार के रथ को चलाने वाले सही सारथियों (नौकरशाही) की बात करें तो वे आशंकित है कि लंका के इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल और केवल एक मात्र कारण 'मुतखोरी' है, वहां की सरकार ने अपने आपको लोकप्रिय बनाए रखने के लिए वहां के नागरिकों को हर जीवनोपयोगी वस्तु मुत उपलब्ध कराई और जब इससे सरकार आर्थिक संकट में आ गई और उसने 'मुतखोरी' रोक दी तो वहां की जनता ने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध शुरू कर दिया और सरकार को इस्तीफें के लिए मजबूर होना पड़ा।

अब हमारे देश के शीर्ष नौकरशाहों का यह नजरिया कहां तक सही है, यह तो वे स्वयं जाने किंतु इसी नजरियें के चलते नौकरशाहों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगाह करना कहां तक ठीक है? सरकार के गोपनीय सूत्रों का कहना है कि लंका की इस स्थिति पर वहां के नौकरशाहों से भारतीय नौकरशाहों ने चर्चा की तब वहां के नौकरशाहों ने जनक्रांति के जो कारण गिनाये उनमें मुख्य कारण सरकार की मुतखोरी की योजनाएं है, जिनके बंद कर दिये जाने पर यह विकट स्थिति पैदा हुई है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने केन्द्रीय शीर्ष नौकरशाहों की बैठक बुलाई तब उस बैठक में नौकरशाहों ने एक स्वर से प्रधानमंत्री को आगाह किया कि भारत में 2014 के बाद से लागू की गई 'मुतखोरी' की योजना-परियोजनाओं को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिये, यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत में भी 'लंका काण्ड' की पुनरावृत्ति हो सकती है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने नौकरशाहों की इस आशंका को सिरे से खारिज तो नहीं किया बल्कि नौकरशाहों से इसी संदर्भ में भारत को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर जानकारी देने को कहा तथा सरकार की मौजूदा नीतियों में खामियों पर सुझाव देने को भी कहा, साथ ही स्वयं ने भी इस मामले में सतर्क रहने का फैसला लिया। मोदी जी की पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की यह केन्द्रीय नौकरशाहों के साथ नौवीं बैठक थी। मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट कहा है कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकल कर अतिशेष के प्रबंधन की नई चुनौति का सामना करें। मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबों का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। इस अवसर पर नौकरशाहों ने भी खुलकर मोदी जी से बातें की, उन्होंने पिछले चुनावों के दौरान एक राज्य में एक लोक लुभावन योजना का जिक्र भी किया तथा ऐसी 'मुतखोरी' की योजनाओं से परहेज करने की भी सलाह दी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हमारे दो पड़ौसी राज्यों पाकिस्तान व श्रीलंका में इन दिनों ''जनक्रांति'' चरम पर है, यद्यपि इस व्यापक जनक्रांति का कारण सत्तासीन लोगों की महत्वाकांक्षा और जनता की उपेक्षा है, श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 'मुतखोरी' की योजनाओं की शुरूआत की और जब इनसे सरकार भीषण आर्थिक संकट में आ गई और मंहगाई चरम पर पहुंच गई तो वहां 'जनक्रांति' हो गई। यही स्थिति पाकिस्तान की भी है, वहां भी राजनीति व आर्थिक कारणों से जनक्रांति का जन्म हुआ। अतः इन्हीं दो पड़ौसी देशों का जिक्र करते हुए भारतीय संदर्भ में नौकरशाहों ने मोदी जी को आगाह किया। (लेखक--ओमप्रकाश मेहता / ईएमएस)

महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी जरूरी है

देश के ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को यदि कोई शारीरिक बीमारी होती है तो वो महिला डॉक्टर के पास जाना ज्यादा पसंद करती हैं उसका सबसे बड़ा कारण उनका सहजता से अपनी समस्या समझा पाना रहता है। ऐसा ही महिलाओं के द्वारा अपनी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराना ज्यादा सहज दिखाई देता है वो अपनी बात महिला पुलिस से ज्यादा आसानी से कर पाती हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले मैं पास के सरकारी अस्पताल में किसी काम से गयी थी। वहाँ एक 10-12 साल की उदास,निढाल, डरी सहमी सी बच्ची एक महिला पुलिस कर्मी से कभी कुछ बात करती, कभी उसके काँधे से लग जाती ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उसकी बहुत नजदीक हो, पास ही खड़ा एक व्यक्ति पानी की बोतल हाथ में लिए बार बार उस महिला पुलिस से उसे पानी देने के लिए पूछ रहा था। वो बच्ची उस व्यक्ति की तरफ कम ही देख रही थी।शायद वो उस बच्ची का पिता था। मैंने कुछ देर बाद उस महिला पुलिस कर्मी से पूछा- क्या हुआ है इसे? क्या ये बच्ची आपकी कोई जानकार है? उसने मुझे उत्तर दिया- नहीं! मैं इस बच्ची को नहीं जानती। मैं बस अपनी डयूटी कर रही हूँ। शायद इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। इसका मेडिकल टेस्ट होना है हम सभी इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्तब्ध थी उस बच्ची को देख जो अपने पिता में एक पुरुष और उस अंजान पुलिस कर्मी में अपनी सी एक महिला की तलाश में सहज होने की कोशिश कर रही थी..। उस बच्ची के उदास चेहरे में महिला पुलिस कर्मी के प्रति सहजता साफ देखी जा सकती थी। उस दिन ऐसा आभास हुआ की महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

वैश्विक राजनीति के परिवेश में महिलाओं की बढ़ती भूमिका कई नये आयाम स्थापित कर रही है, जो सामाजिक न्याय व्यवस्था के बेहतर भविष्य की आधारशिला हो सकती है।

वर्षो से शक्ति,सहभागिता और सत्ता का गठजोड़ सामाजिक परिवर्तन का आधार बना है। सत्ता के समीकरण को साधने में अहम हिस्सेदार देश की महिलाएं रही हैं जो कई बार देश में किंग मेकर का काम करती हैं परंतु सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न के बराबर ही है। समाज के कई अहम मुद्दों के समाधान में अपने जुझारू व्यक्तित्व का परिचय देने के बाद भी, देश की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का रुझान अब तक महिलाओं को महिला वोट बैंक से ज्यादा ऊपर नहीं उठा सका है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूँढने के लिए हमें कई मुद्दों पर खुल कर बात करनी होगी। जिनसे देश की आधी आबादी राजनीति में अपनी बराबर की दावेदारी पेश कर पाए। तभी सही मायने में महिलाओं से जुड़े शिक्षा, समाज, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे हल हो पाएंगे।

आज देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। आजादी के 75 साल बाद समाज में क्रांतिकारी बदलाव देखे जा सकते हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ कर रोजगार में सहभागी बन रही हैं। महिलाएं मजदूर भी हैं और रिक्शा चालक भी साथ ही सरकारी नौकरी से सेना तक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं लेकिन उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इससे उनकी समस्याएं जो पहले घर में ही दफन हो जाती थी अब बाहर खुलकर तो आ रही हैं लेकिन समाधान की दहलीज पर आकर सिमट जा रही हैं जिस तरह से उनका निराकरण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का ग्राफ इस बात की गवाही देता है यदि समाज और सरकार को महिलाओं की समस्या का पुख्ता हल ढूँढना है तो समय रहते देश में महिलाओं का शिक्षा, व्यवसाय, सिविल सेवा,सेना और संसद में प्रतिशत बढ़ाना होगा।

आजादी के 75 साल बाद भी महिलाएं आखिर कहाँ खड़ी हैं? जब हम इस विषय पर गौर करते हैं तो समाज में महिलाओं को लेकर कई चिंताएं जाहिर होती हैं, कई समस्याएं हैं जिनके सवाल दुनियाभर के समाज वैज्ञानिक तलाशने में लगे हैं हम महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना ही अपनी पीठ थपथपा लें लेकिन हमें गौर करना होगा कि अभी भी एन सी आर बी के आकड़ों में उछाल कम नहीं हुआ है। उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जिसमें सुधार लाना समाज और सरकारों का अहम् मुद्दा होना चाहिए।

इसके सुधार का एक रास्ता महिलाओं की सत्ता और सरकार में बढ़ती भागीदारी से भी होकर गुजरता है। अक्सर चुनाव के पहले महिलाओं के सत्ता में प्रतिनिधित्व पर बढ़ चढ़ कर बहस होती है लेकिन चुनाव आते आते महिलाओं की हिस्सेदारी कई वजहों से कम होने लगती है, ज्यादातर राजनीतिक दलों से उन्हें उम्मीदवाद नहीं बनाया जाता, सबकी अपनी अपनी दलीलें होती हैं जिसका सीधा परिणाम सरकार में उनकी हिस्सेदारी कम कर देती है। हमें इस विषय पर खुल कर सोचना होगा। महिलाएं जब किंग मेकर हो सकती है तो फिर किंग क्यों नहीं?

वर्तमान समय में देश के 28 राज्यों में से केवल एक राज्य में ही महिला मुख्यमंत्री हैं। देश में ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज, नजमा हिपतुल्ला आदि अनेकों महिलाओं ने आपने राजनैतिक जुझारू प्रतिनिधित्व से यह साबित किया है की वो समाज, प्रदेश और राष्ट्र का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल पूरे होने के पड़ाव पर हमें केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री मिली और वो भी मजबूत राजनैतिक परिवार से संबंध रखती थी। संभवतः यदि वो भी किसी सामान्य परिवार से होती तो हम अभी भी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की कमी को भरने के इंतजार में होते। देश की महिलाओं ने अपनी काबिलियत से राष्ट्रपति, वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे जिम्मेदार पदों को बखूबी संभाला है।

निश्चित तौर पर अभी हाल ही में देश के पांच राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पंजाब में पहले के मुताबिक महिलाओं की दोगुनी संख्या हो गयी है। पंजाब में 117 सीटों में 13 महिला हैं जबकि पहले केवल 6 थी। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 46 महिलाओं को चुना गया है। उत्तराखंड में 70 सीटों में 8 महिलाएं हैं, मणिपुर में 60 सीटों में 5 महिलाएं चुनी गई और गोवा में 40 सीटों में 3 महिलाएं ही आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी। आजादी की पहली जंग में तलवार से बंदूक तक, स्वतंत्रता की लड़ाई में खूफिया तंत्र से पैदल मार्च तक, लाठियों से लेकर गोलियां तक खाने में महिलाओं ने बराबर से सहभागिता की है। इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाएं इस बात की तसदीक करती हैं लेकिन अभी भी उनका आधा प्रतिनिधित्व पाना बाकी है।

र्नीं की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भूमिका के साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भी 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। वर्तमान लोकसभा में 78 और राज्य सभा में 25 महिला सांसद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दोनों सदनों में महिला प्रतिनिधि के तौर पर केवल 103 महिला सदस्य हैं यानी 13 फीसदी जबकि विश्व के कई देशों में इसमें काफी अंतर है जैसे दक्षिण अफ्रीका में 43 फीसदी, रवांडा में 62 फीसदी, अमेरिका में 24 फीसदी, ब्रिटेन में 32 फीसदी, और बांग्लादेश में 21 फीसदी है।

इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मुताबिक भी राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की भूमिका में भारत का 148वां स्थान है। ऐसे में यह प्रश्न उठना वाजिब है कि यदि महिलाओं के लिए कोई कानून पास होता है तो उसमें महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर न्याय हो सके। जैसा की महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम उम्र पर सिफारिश देने वाली संसदीय समिति के गठन में होना चाहिए था जहाँ 31 सदस्यों में से सिर्फ एक महिला सांसद थी। महिलाओं की समस्या और समाधान पर महिलाओं को अपना पक्ष रखना होगा। वर्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 18वें स्थान पर है।

वर्तमान में भारत की साख और धाक दुनिया में तेजी से बढ़ी है ऐसे में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए महिला प्रतिभागियों को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। भारत की आधी आबादी को संसद व राज्य विधान मंडलों में एक तिहाई आरक्षण दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सर्वसम्मति बनाते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिये, जिसमें महिलाओं के लिये 33ऱ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व खुद ब खुद बढ़ जाएगा, जैसा कि पंचायतों में देखा जा सकता है। देश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों और शहरी निकायों में 1993 से 33ऱ आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढे इसके लिए महिलाओं को स्वम् आगे आना होगा राजनीति में अपनी रुचि को और बढ़ाना होगा। लड़कियों को कॉलेज के दौरान ही छात्र राजनीति का अहम् हिस्सा बनना होगा साथ ही सभी पार्टियों को योग्य महिला उम्मीदवार को टिकट देना होगा इससे न केवल भारत की साख मजबूत होगी बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। (लेखक-- डॉ. नाज़ परवीन / ईएमएस)

आज का इतिहास 8 अप्रैल

1774 माधवराव द्वितीय का जन्म हुआ. उन्हें दस दिन की उम्र में ही गद्दी पर बैठा दिया गया.

1831 समाज सुधारक राममोहन राय इंग्लैंड पहुंचे.

1857 आजादी की लड़ाई की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई.

1894 प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का निधन.

1939 इतावली सेना के हमले के बाद अल्बानिया नरेश जोग देश छोड़कर भाग गये.

1958 परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के लिए अमरोका ने आपसी निरीक्षण का प्रस्ताव किया.

1961 अल्जोरियायी विद्रोहियों के साथ शांतिपूर्ण समझौते का फ्रांसीसी जनमत सग्रह ने समर्थन किया.

1986 लेबनान के राष्ट्रपति अमीन गमाएल की पार्टी के कार्यालय के पास कार बम विस्फोट में दस व्यक्ति मरे और 110 घायल हुए.

1996 माधवराव सिंधिया, जी. के. मूपनार नटवर व चिदंबरम सहित अनेक नेता कांग्रेस पार्टी से निष्कासित.

1997 हवाला मामले में अभियुक्त भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी व कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त किया.

धर्म या जाति के आधार पर किसी राजनैतिक दल का समर्थन या विरोध अनुचित

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घोषित होने के बाद प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र से एक अप्रत्याशित एवं अफ़सोसनाक ख़बर आई। ख़बरों के अनुसार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने पर बाबर नामक एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठघरही गांव में बाबर के रिश्तेदारों ने ही उसे पीट-पीटकर मार डाला। बाबर का 'क़ुसूर' यह बताया जाता है कि उसने विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। बाबर के रिश्तेदार कथित तौर पर उससे इसीलिये नाराज़ थे क्योंकि वह भाजपा के लिये चुनाव प्रचार कर रहा था। उसके रिश्तेदार बाबर से तब और भी नाराज़ हो गये थे जब उसने भाजपा की जीत पर गांव में मिठाई बांटी थी। इसी के बाद उन्होंने बाबर की जमकर पिटाई कर दी। जिससे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत गयी। मरणोपरांत उसके जनाज़े को कन्धा देने के लिये भाजपा विधायक पी एन पाठक कई पार्टी समर्थकों के साथ पहुंचे। समाचारों के अनुसार इस मामले पर ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक जताते हुए मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विधायक पाठक ने कहा है कि-' इस मामले में कोई भी दोषी बख़्शा नहीं जाएगा, ढूंढवा कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी नस्ल दोबारा ऐसी घटना करने की जुर्रत नहीं कर पाएगी'। कुछ आरोपी गिरफ़्तार भी किये जा चुके हैं।

इसी तरह की कुछ ख़बरें बदायूं,कानपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर से भी प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि कहीं किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाने का विरोध सहना पड़ा तो कहीं भाजपा की जीत की ख़ुशी में मिठाई बांटने का तो कहीं अपने घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र का चित्र लगाने का। भारतीय लोकतंत्र में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसी भी विचारधारा के किसी भी राजनैतिक दल का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार हो वहाँ इस प्रकार के पूर्वाग्रह व इस तरह की हिंसक घटनाओं अथवा धमकियों को किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त लगभग सभी घटनाओं का राज्य प्रशासन व स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया जा रहा है। बाबर की हत्या की घटना को तो मोहम्मद अख़लाक़,पहलू ख़ान,तबरेज़ व जुनैद आदि अनेक लोगों के साथ घटी 'मॉब लिंचिंग' जैसी घटना भी कहा सकता है। सरकार व प्रशासन का ऐसे मामलों में सख़्ती दिखाना स्वागत योग्य क़दम है।

भारतीय जनता पार्टी भले ही मुस्लिम विरोध के नाम पर बहुसंख्य मतों को ध्रुवीकृत करने की रणनीति पर केंद्रित राजनीति क्यों न करती हो। और मुसलमानों की बहुसंख्य आबादी भी भाजपा को मुस्लिम विरोधी दाल क्यों न स्वीकार करे। परन्तु भाजपा में मुसलमानों का दख़ल कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले आरिफ़ बेग 1973 में जनसंघ से जुड़े थे। वे बीजेपी के एक क़द्दावर नेता थे। 1977 लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर बेग ने भोपाल से चुनाव लड़ा था और डॉ. शंकर दयाल शर्मा जो कि आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने,को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। बेग 1989 में बैतूल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते । आरिफ़ बेग मोरारजी देसाई की सकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे थे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक संस्थापक सदस्य का नाम था सिकंदर बख़्त। जनता पार्टी से 1980 में अलग होकर जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो सिकंदर बख़्त इसी पार्टी में शामिल हुए और भाजपा के पहले मुस्लिम महासचिव बनाए गए। 1984 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नातिन नजमा हेपतुल्लाह 2004 में बीजेपी में शामिल हुईं। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया। वे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनीं। और बाद में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया। एमजे अकबर, मुख़्तार अब्बास नक़वी,शहनवाज़ हुसैन और ज़फ़र इस्लाम जैसे कई मुस्लिम नेता आज भी भाजपा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी सेवायें दे रहे हैं। परन्तु चूंकि यह स्थापित व ऊँचे क़द के नेता हैं इसलिये शायद भाजपा विरोधी पूर्वाग्रह रखने वाले मुसलमानों के विरोध के स्वर इनके विरुद्ध बुलंद नहीं हो पाते।

ऐसा भी नहीं है कि धर्माधारित राजनैतिक विरोध सिर्फ़ मुसलमानों तक ही सीमित है। याद कीजिये जब भाजपा की एक साध्वी कही जाने वाली सांसद ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि रामज़ादे भाजपा को वोट देंगे और 'हराम ज़ादे ' भाजपा के विरोध में। क्या अर्थ है इस वाक्य का ? आख़िर धर्माधारित विरोध का ही तो यह भी एक अंदाज़ है ? इसी तरह उत्तर प्रदेश के ताज़ातरीन विधानसभा चुनावों में सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक अत्यंत विवादित व अमर्यादित बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि -'जो हिन्दू उन्हें छोड़कर किसी और को वोट देगा वो उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि उसमें हिन्दू का ही ख़ून है या फिर मुसलमानों का ख़ून है'। राघवेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने सख़्ती दिखाते हुये 24 घंटे तक उसके चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लगाई थी। उसका यह बयान हिन्दू मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाने तथा मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश के साथ डराने धमकाने व भय फैलाने का प्रयास है अथवा नहीं। इसी तरह यदि आप तेलंगाना विधानसभा में गोशामहल के भाजपा विधायक राजा सिंह के 'विचार ' सुनें तो ऐसा लगेगा कि उनकी पूरी राजनैतिक कमाई ही मुस्लिम विरोध पर आधारित है। भाजपा में ही ऐसे तमाम नेता भरे पड़े हैं जो संघ की नीतियों के अनुसार मुसलमानों ,अल्पसंख्यकों,ईसाईयों तथा कंम्यूनिस्टों को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। परन्तु उनके विरुद्ध कार्रवाई करना तो दूर उल्टे उनकी प्रोन्नति होती देखि जा सकती है।

हो सकता है राजनैतिक उपलब्धियां हासिल करने का यह 'सांप्रदायिक शार्ट कट' नेताओं को रास आता हो परन्तु लोकतंत्र के एक सच्चे प्रहरी व देश की एकता अखंडता व सद्भाव के रक्षक होने के नाते किसी भी धर्म व जाति के आम मतदाताओं का धर्म व जाति के आधार पर किसी राजनैतिक दल का समर्थन या विरोध करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। (लेखक- तनवीर जाफ़री / ईएमएस)

शब्द पहेली - 7249

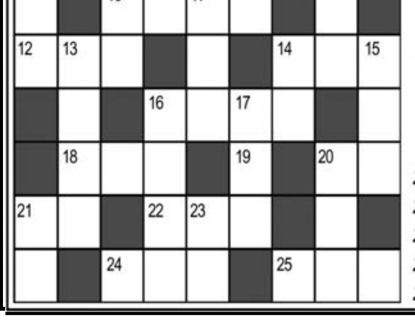

बाएँ से दाएँ

1. तन,शरीर-3
3. चकोर,चंद्रप्रेमी पक्षी-3
6. झगड़ा,द्वेष-3
7. मोटा आटा-2
8. खिंचाव,स्वर विस्तार-2
9. असली,शुद्ध-3
10. यंत्रशाला-4
12. कार्यविधि-3
14. चिंगारी-3
16. एक कंद जिसे सुखा कर सौंठ बनाई जाती है-4
18. दूल्हे की पगड़ी-3
20. सम्मान-2
21. प्राण,जीवन तत्व-2
22. कुशल,होनहार-3
24. राशिचक्र की एक राशि-3
25. प्रेमी,साजन- 3

ऊपर से नीचे

2. अवलोकन,दरस-3
3. चलने का ढंग-2
4. तलघर-4
5. इस पर रोटी सेंकते हैं-2
6. जलजला-3
7. रसीला,रस से भरपूर-4
8. बल,जोर,दम-3
10. चाचा,अंकल-2
11. शौहर,पति-3
13. 'दीवाने हुए पागल' की नायिका-2,2
14. वहम,संदेह-3
15. राजा,सम्राट-3
16. उपद्रवी,आतंकी-4
17. गिरवी रखी वस्तु-3
20. बैठने की जगह-3
21. शराब का प्याला-2
23. रांझे की प्रेमिका-2

शब्द पहेली -7248 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल-समाचार

दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर डु प्रीज ने एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा

जोहान्सबर्ग (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिग्नॉन डु प्रीज ने एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आठ साल तक टीम की कमान संभालने के बाद डु प्रीज ने टी-20 क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने और परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए यह कदम उठाया है। डु प्रीज ने नवंबर 2014 में टीम का नेतृत्व संभाला था। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम साल 2014 के बाद से अब पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रही है। टीम को अब इस अनुभवी खिलाड़ी के बिना ही इंग्लैंड के दौरे पर जाना होगा।

डू प्रीज ने अपने एक बयान में कहा, 'मैं अब तक चार आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप में खेली, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूं। ये मेरे जीवन की कुछ सबसे अच्छी यादें हैं, हालांकि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देती हूं और अब जल्द ही अपना परिवार बनाना चाहती हूं।' इस पूर्व कप्तान ने कहा, 'मुझे लगता है कि खेल के लंबे प्रारूप से अलविदा कहने और ओर टी-20 प्रारुप पर ध्यान देने का यही सही समय है।

इस खिलाड़ी ने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड में विश्व कप अभियान पूरा होने पर एकदिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया था। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट बहुत अच्छी स्थिति में है और यह समय पीछे हटने और रोमांचक क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को आगे लाने का समय है।' डु प्रीज ने साल 2007 में पदार्पण करते हुए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत के बाद से कुल 154 मैचों के साथ सबसे अधिक मैच खेलने वालीं दक्षिण अफ्रीकी महिला खिलाड़ी की उपलब्धि अपने नाम की है। इस खिलाड़ी के नाम कुल 3760 रनों के साथ ही एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। उन्होंने इनमें से 46 मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की। उन्होंने एकमात्र टेस्ट मैच 2014 में भारत के खिलाफ मैसूर में खेला था, जहां उन्होंने पहली पारी में शतक बनाया था। हाल ही में संपन्न 2022 महिला वनडे विश्व कप में डु प्रीज ने मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी 150वां अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेलते हुए अपने करियर का 18 अर्द्धशतक लगाया था।

प्रो हॉकी लीग में आज भारत और नीदरलैंड के बीच होगा पहला मुकाबला

भुवनेश्वर (ईएमएस)। नीदरलैंड महिला हॉकी टीम महिला एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गई। यहां उसे भारतीय टीम के खिलाफ आठ और नौ अप्रैल को कलिंग हॉकी स्टेडियम में दो मैच खेलने हैं। टीम की कप्तान यिब्बी जानसेन ने कहा है कि उनकी टीम भारत से खेलने को लेकर उत्साहित है।

जानसेन ने कहा कि हम यहां भारत में आने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम इस खास अनुभव के लिए तैयार हैं। हमारा प्यार भरे तरीके से स्वागत किया गया। वहीं टीम कोच जोस्ट बिटरलिंग ने इस बारे में कहा कि हम सच में यहां खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर इस टीम के साथ।

नीदरलेंड अभी 2021-22 महिला एफआईएच हॉकी प्रो लीग के पूल टेबल छह मैचों में 17 अंकों के साथ शीर्ष पर है। उसने अब तक पांच सीधी जीत और एक मैच पेनल्टी शूटआउट में जीता है। कप्तान जानसेन ने प्रो लीग में टीम के अब तक प्रदर्शन के बारे में कहा कि हम सभी अलग-अलग देशों के खिलाफ इन सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों को खेलकर बहुत खुश हैं। हमारा प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। हम अपने खेल से खुश हैं।

कोच बिटरलिंग ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम की तैयारियों के बारे में कहा कि मैं टीम की तैयारी से संतुष्ट हूं। हमारी टीम में अनुभवी के साथ ही कुछ युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले दो सप्ताहों में एक साथ प्रशिक्षण लिया है और अब हमारा लक्ष्य भारतीय टीम के खिलापफ बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा।

सिंधू कोरियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

लक्ष्य और मालविका हारे

सुनचियोन (ईएमएस)। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी हैं। ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी। सिंधू ने ओहोरी को एकतरफा मुकाबले में 21-15 21-10 से हराया।

इसी के साथ ही ओहोरी के खिलाफ अब तक हुए सभी 12 मुकाबलों में सिंधू को जीत मिली है। अब तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधू का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान से होगा। इस मुकाबले में सिंधू का पलड़ा भारी है। सिंधु ने ओंगबामरुंगफान के खिलाफ अब तक खेले गये 17 में से 16 मुकाबले जीते हैं और उसे केवल एक बार ही हार झेलनी पड़ी है। वहीं भारत के ही लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ दूसरे दौर में हार के साथ ही बाहर हो गयी है।

लक्ष्य को पुरुष एकल में अपने से कम रैंकिंग वाले इंडोनेशिया के शेसार हिरेन रुस्तावितो ने सीधे गेम में 20-22 9-21 से हराया जबकि मालविका को महिला एकल के दूसरे दौर में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग ने 8-21 14-21 से पराजित किया।

एक अन्य मुकाबले में सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की मिश्रित युगल जोड़ी भी हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी को ओउ शुआन यी और हुआंग या कियोंग की चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी के हाथों तीन गेम में 20-22 21-18 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। सिंधू को 37 मिनट चले दूसरे दौर के मुकाबले में जीत के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहले गेम में ओहोरी केवल एक बार हल्की बढ़त बनाने में सफल रही।

सिंधू ने इसके बाद वापसी करते हुए पहला गेम आसानी से जीत लिया। जापानी खिलाड़ी ने दूसरे गेम में वापसी का प्रयास किया पर सिंधू ने अगले 19 में से 17 अंक जीतकर गेम और मैच अपने नाम किया।

क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया पर जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

पोटचेफस्ट्रूम (ईएमएस)। भारतीय टीम यहां जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को अपने से कम रैंकिंग वाली दक्षिण कोरिया पर जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से अब तक पूल डी के सभी तीन मैच जीतकर अधिकतम नौ अंक हासिल किये हैं। भारतीय टीम ने वेल्स, जर्मनी और मलेशिया के खिलाफ मैचों में आसान जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इन तीन मैच में कुल मिलाकर 11 गोल किए जबकि केवल दो गोल खाये हैं। वहीं दूसरी ओर कोरिया की टीम ग्रुप सी में केवल तीन अंक हासिल करने के बाद भी बेहतर गोल अंतर होने के कारण दूसरे स्थान आई है। कोरिया के पूल में अर्जेन्टीना की टीम ने अधिकतम नौ अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है।

वहीं उरूग्वे और आस्ट्रिया के कोरिया के समान ही तीन अंक रहे पर बेहतर गोल अंतर के कारण एशियाई टीम को जीत मिली है। भारतीय टीम में कप्तान सलीमा टेटे के अलावा स्ट्राइकर शर्मिला देवी और लालरेमसियामी के रूप में तीन ओलंपियन खिलाड़ी शामिल हैं जिससे उसका पलड़ा भारी नजर आता है। सलीमा ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मौके बनाए हैं। इसके अलावा शर्मिला और लालरेमसियामी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा हैं। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से युवा स्ट्राइकर मुमताज खान ने मलेशिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगायी थी। मुमताज ने अब तक कुल पांच गोल दागे हैं जबकि लालरेमसियामी और लालरिंडिकी ने तीन मैच में दो-दो गोल किए हैं। संगीता कुमारी और ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने एक-एक गोल किया। इसके बाद भी कप्तान सलीमा कोरियाई टीम को कम नहीं आंक रही हैं।

सलीमा ने कहा, ''हमारे पास तेज गति से खेलने वाली कई खिलाड़ी हैं। इसलिए हम इस मैच में जीत के प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। इसके बाद भी हमें कोरिया के खिलाफ पूरी ताकत से उतरना होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इंग्लैंड की टीम अमेरिका से खेलेगी। वहीं अर्जेन्टीना को जर्मनी से खेलना होगा।

कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की योजना बना रही कंपनियां

मुंबई (ईएमएस)। कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के साथ देश की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आई है। इससे घरेलू कंपनियों की कमाई पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। कमाई बढ़ने के कारण कंपनियां नई भर्तियां करने के साथ इस साल अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है। हालांकि, यह इंक्रीमेंट कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा होगा है, जबकि औसत प्रदर्शन वाले कर्मचारियों की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है।

सैलरी रिपोर्ट-2022 में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां निवेश को लेकर अधिक सकारात्मक हैं, विशेषतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा। सकारात्मक निवेश दृष्टिकोण के कारण इस साल कर्मचारियों की सैलरी में 8-12 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य सैलरी हाइक 9 फीसदी रहने की संभावना है। महामारी से पहले 2019 में भारतीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 7 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसमें आगे कहा गया है कि यूनिकॉर्न के साथ मिलकर स्टार्टअप और नए जमाने की कंपनियां सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ाएंगी।ये कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी औसतन 12 फीसदी बढ़ा सकती हैं।

इस साल जिन सेक्टर में सैलरी बढ़ने की संभावना है,उसमें प्रमुख रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ई-कॉमर्स और डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे अन्य क्षेत्रों में भी सैलरी बढ़ेगी. कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले कर्मचारी सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर ज्यादा मोलभाव करने की स्थिति में रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा साइंटिस्ट (विशेष रूप से मशीन लर्निंग से परिचित), वेब डेवलपर्स और क्लाउड आर्किटेक्ट की भी अत्यधिक मांग रह सकती है।

बीएसई टेक्नोलॉजी को केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के रुप में काम करने को मंजूरी

मुंबई (ईएमएस)। शेयर बाजार बीएसई की अनुषंगी बीएसई टेक्नोलॉजी को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए) के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। केआरए सेबी द्वारा विनियमित इकाई है, जो बाजार प्रतिभागियों को निवेशकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानना) का अधिकार प्रदान करती है। प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए केवाईसी अनिवार्य होता है। बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा, बीएसई को केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के तौर पर काम करने की मंजूरी देने के लिए सेबी का आभार। केवाईसी केआरए प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के लिए अहम हिस्सा है और इसी के साथ निवेशक की प्रतिभूति बाजार में यात्रा की शुरुआत होती है।''

सोने में तेजी

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई है। गुरुवार को सोने का वायदा भाव 42 रुपये की तेजी के साथ 51,638 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का जून डिलीवरी वाले अनुबंध का भाव 42 रुपये करीब 0.08 फीसदी की तेजी के साथ 51,638 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 17,898 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं बाजार जानकारों के अनुसार कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली (खरीदारी) करने से सोना वायदा कीमतों में तेजी आई है।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार गुरुवार को भी गिरावट के साथ बंद हुआ। यह लगातार तीसरा दिन है जब बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। बाजार में यह गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनियों एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के टूटने से आई है। इस कारण दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 575.46 अंक करीब 0.97 फीसदी नीचे आकर 59,034.95 अंक पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान एक समय यह 633.06 अंक तकरीबन 1.06 फीसदी तक लुढ़क गया था पर बाद में इसमें सुधार आया।

वहीं पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 168.10 अंक तकरीबन 0.94 फीसदी नीचे आकर 17,639.55 अंक पर बंद हुआ। सबसे अधिक नुकसान में टाइटन, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और पावरग्रिड के शेयर रहे। वहीं एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और डा. रेड्डीज के शेयर ऊपर आये हैं।

निष्क्रिय ईपीएफ खातों में 3930.85 करोड़ जमा

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में निष्क्रिय खातों में कुल 3930.85 करोड़ रुपए जमा हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा ?कि कर्मचारी भविष्य निधि में बिना दावे वाली कोई जमा राशि नहीं है। यादव ने कहा ?कि ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित रूप से दावेदार हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ऐसे निष्क्रिय खातों में कुल जमा धनराशि 3930.85 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 18,62,128 है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर 2020 के बाद इन प्रतिष्ठानों द्वारा 1,44,82,359 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई। उन्होंने बताया कि पंजीकृत प्रतिष्ठानों की सबसे ज्यादा संख्या (2,97,684) महाराष्ट्र में है जबकि दिल्ली में 1,14,151; गुजरात में 1,37,686 ; तामिलनाडु में 1,67,390 तथा उत्तर प्रदेश में 1,47,790 प्रतिष्ठान ईपीएफओ से पंजीकृत हैं।

कॉल ड्राप की समस्या से निपटने दूरसंचार कंपनियों पर सख्ती करेगी सरकार

- कॉल ड्रॉप की समस्या सुलझाने में विफल होने पर दूरसंचार कंपनियां का लाइसेंस हो सकता है रद्द

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार दूरसंचार कंपनियों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि कॉल ड्रॉप एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों पर विचार किया जाएगा। इस बात पर भी विचार हो सकता है कि अगर दूरसंचार कंपनियां कॉल ड्रॉप की समस्या सुलझाने में विफल रहती हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी इन कंपनियों की ओर से प्रस्तुत क्वार्टरली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर कर रहा है। भारत में टीएसपी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके मोबाइल नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप की समस्या ट्राई के निर्धारित बेंचमार्क के दायरे में रहे। इस संबंध में ट्राई ने 'द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ बेसिक टेलीफोन सर्विसेज (वायरलाइन) एंड सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (पांचवां संशोधन) रेगुलेशन-2019' नाम से अधिसूचना भी जारी की है। यह एक अक्टूबर 2017 से लागू है।

समस्या से निपटने की नीतिगत पहल

"- दूरसंचार विभाग ने गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिहाज से बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं।

- इनमें ट्रेडिंग की अनुमति देना, शेयरिंग, स्पेक्ट्रम उदारीकरण, एक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की अनुमति देना, टावर लगाने के लिए सरकारी जमीन/बिल्डिंग उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।
- देशभर में मार्च 2014 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान टीएसपी की ओर से 2जी/3जी/4जी-एलटीई सेवाओं के लिए करीब 16.82 लाख अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) जोड़े गए हैं।
- कॉल ड्रॉप पर ग्राहकों से सीधी प्रतिक्रिया लेने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया है।
- इसमें दिसंबर 2016 से करीब 5.67 करोड़ ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया है। इनमें 73.61 लाख ग्राहकों ने सर्वे में हिस्सा लिया है।
- समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए टीएसपी के साथ फीडबैक साझा किया जाता है। इससे कॉल ड्रॉप से जूझ रहे करीब 1.73 लाख मामलों का समाधान हो चुका है।

झारखंड में वाणिज्य कर संग्रह 25 प्रतिशत बढ़कर 19,750 करोड़ हुआ

रांची (ईएमएस)। झारखंड में वित्त वर्ष 2021-22 में वाणिज्य कर संग्रह में 25 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई और यह वर्ष 2020-21 में एकत्रित 16,147 करोड़ रुपए से बढ़कर 19,750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस रिकॉर्ड कर संग्रह के लिए कर विभाग के 17 अधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। झारखंड की वाणिज्य कर विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 19,750 करोड़ रुपए का वाणिज्य कर संग्रह किया, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2021-22 में 18,422 करोड़ रुपए के वाणिज्य कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाणिज्य कर संग्रह इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक है। राज्य में पहली बार इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यु एनालिसिस विंग का गठन कर क्षेत्रवार कर संग्रहण का विश्लेषण किया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।

दिल्ली में सीएनजी की कीमत ढाई रुपए प्रति किलो बढ़ी

- मार्च से अब तक दाम कुल 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े

नई दिल्ली (ईएमएस)। ?दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी महंगी हुई है। सीएनजी के दाम 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं जिसके साथ मार्च से अब तक दाम कुल 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में सीएनजी की कीमत 66.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 69.11 रुपए प्रति किलो हो गई है। आईजीएल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस (पीएनजी) की खुदरा बिक्री करती है। बुधवार को भी सीएनजी की कीमत में 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। पाइप से रसोई गैस (पीएनजी) की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 41.61 रुपए प्रति इकाई है। मार्च के बाद से दिल्ली में सीएनजी के दामों में 12.48 प्रति किलो की वृद्धि की गई है।

महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमत सात रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 67 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि गुजरात गैस ने दरों में 6.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर इसे 76.98 रुपए कर दिया। मूल्यवर्धित कर (वैट) जैसे स्थानीय करों की वजह से कीमतें शहर-दर-शहर अलग अलग होती हैं। सरकार ने एक अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमतों को दोगुना से अधिक कर 6.1 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (प्रति इकाई) कर दिया है। इसके बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि हुई है।सीएनजी की कीमतों में यह वृद्धि पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और रसोई गैस एलपीजी की दरों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि के बाद हुई है।

रूसी सेना 10 मानवीय गलियारों पर सहमत हुई

ल्वीव (ईएमएस)। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूसी सेना उनके देश के तीन पूर्वी क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षित तौर पर निकासी के लिए 10 मानवीय गलियारों पर सहमत हुई। आने वाले दिनों और हफ्तों में यूक्रेन के औद्योगिक पूर्वी क्षेत्र पर कब्जे के लिए रूस के अपने सैन्य हमले तेज करने की उम्मीद है, इसके बाद कीव ने इसे रोकने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से और हथियार मुहैया करने की अपील की है। उप प्रधानमंत्री इरयाना वेरेशचुक ने कहा कि दोनेत्स्क, लुशांक और जपोरीझझीया क्षेत्रों से नागरिकों को निकाल कर अन्य शहरों में ले जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मारियोपोल और एनेरहोदार से जपोरीझझीया कार के जरिये तथा बर्दीस्क, तोकमाक और मेलीतोपोल से कार एवं बसों के द्वारा यात्रा करना संभव होगा।

पड़ोसी और बड़े भाई के रूप में भारत ने हमेशा हमारी मदद कीः पूर्व क्रिकेटर जयसूर्या

- जयसूर्या ने देश में आर्थिक संकट के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया

कोलंबो (ईएमएस)। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने अपने देश के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। पूर्व क्रिकेटर ने भारत को बड़ा भाई बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पड़ोसी और बड़े भाई के रूप में भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। हम भारत सरकार और पीएम मोदी के आभारी हैं। हमारे लिए, मौजूदा परिदृश्य के कारण जीवित रहना आसान नहीं है। हम भारत और अन्य देशों की मदद से इससे बाहर निकलने की उम्मीद करते हैं। जयसूर्या ने कहा कि देश के लोग कई महीनों से इस स्थिति से गुजर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस स्थिति से गुज़र रहे हैं। वे इस तरह जीवित नहीं रह सकते और विरोध करना शुरू कर दिया है। गैस की किल्लत है और घंटों बिजली की आपूर्ति नहीं है। लोगों ने अब श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। वे सरकार को दिखा रहे हैं कि वे पीड़ित हैं। इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। स्थिति को ठीक नहीं किया गया तो ये आपदा में बदल जाएगी। पूर्व क्रिकेटर ने लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने वाले असली लोग हैं, वे सरकार को बता रहे हैं कि वे पीड़ित हैं।

जयसूर्या ने देश में आर्थिक संकट के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जिम्मेदारी सरकार की है। श्रीलंका के लोगों में बहुत आस्था और विश्वास था। वर्तमान सरकार ने जो किया है वो पिछले तीन से चार महीने में अच्छा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से यह सब लोग वर्तमान सरकार को दोष दे रहे हैं।

कीव से हटकर पूर्वी हिस्से डोनबास पर हमले तेज कर रही रुसी सेना

कीव (ईएमएस)। रूस ने राजधानी कीव के बाहरी इलाकों से अपनी फौज हटा ली है, लेकिन वह पूर्वी हिस्से डोनबास पर हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों से जल्द जल्द वहां से निकल जाने को कहा है। दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल के मेयर ने कहा कि वहां पांच हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बीच उत्तरी इलाकों में यूक्रेनी अधिकारी रूस के जुल्मों के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं जहां इस तरह के संकेत मिले हैं कि मॉस्को के सैनिकों ने जाते वक्त पिछले कई दिनों में लोगों की हत्याएं की हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगाह किया कि रूसी सेना पूर्वी हिस्से में नए सिरे से हमला करने की तैयारी कर रही है। क्रेमलिन ने कहा है कि उसका लक्ष्य डोनबास को 'मुक्त' कराना है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, हम लड़ने वाले हैं, और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम तब तक खुद की रक्षा करने के लिए हर मुमकिन विकल्प अपनाएंगे जबतक रूस संजीदगी से शांति की कोशिश शुरू नहीं करता।

यूक्रेन के अधिकारियों ने डोनबास में रहने वाले लोगों से तुरंत वहां से निकल जाने को कहा है। उप प्रधानमंत्री इरयाना वेरेशचुक ने कहा, बाद में लोग मुसीबत में आ जाएंगे और हम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि रूस की लड़ाई में क्षतिग्रस्त हुई सेना को फिर से संगठित होने और पूर्वी यूक्रेन पर चढ़ाई करने में एक महीने तक का वक्त लग सकता है। इस बीच अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने कथित युद्ध अपराधों को लेकर क्रेमलिन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।

मारियुपोल के मेयर वदीम बायोचेन्को ने बताया कि रूस की बमबारी और अन्य लड़ाई में पांच हजार से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई है जिनमें 210 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि रूसी बलों ने अस्पतालों पर बमबारी की है जिससे एक अस्पताल में 50 लोगों की मौत जलने से हो गई। बायोचेन्को ने बताया कि शहर का 90 फीसदी से ज्यादा बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है।

यात्री विमानों को एक मील प्रति सेकेंड की गति से उड़ने की तैयारी में जुटा चीन

बीजिंग (ईएमएस)। बीजिंग में स्थित स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एक स्पेस प्लेन के विकास के साथ इस संभावना को भी हकीकत में उतारने की कोशिश में लगी है कि यात्री विमानों को एक मील प्रति सेकेंड की गति पर आसमान में उड़ाया जा सके। जो अब तक दुनिया के सबसे तेज यात्री विमान माने जाने वाले कॉनकॉर्ड की गति से दोगुना से अधिक है। कंपनी ने एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। जिसमें यात्रियों को बिना किसी कोई हेलमेट या स्पेससूट के दिखाया गया है। इसमें एक एक 12-सीटर स्पेस प्लेन की एनिमेटेड तस्वीर दिखाई गई है, जो एक डेल्टा-आकार का स्पेस प्लेन है। इसके साथ दो टाइटैनिक बूस्टर रॉकेट से जुड़े हैं।

ये स्पेस प्लेन आकाश में एक रॉकेट की तरह से लांच होता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्पेस प्लेन अपने बूस्टर से अलग हो जाता है। फिर ये स्पेस प्लेन 7,000 किलोमीटर (4,350 मील) प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा करके एक तिपाई जैसी संरचना की मदद से अपने गंतव्य पर सीधे उतरता है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का लक्ष्य 2025 में अपनी पहली सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म टेस्ट फ्लाइट शुरू करना है। इसके बाद 2030 तक पूरे तौर पर वैश्विक हाइपरसोनिक प्लेन की उड़ान होगी।

यदि यह पहल साकार होती है, तब यह अंतरिक्ष पर्यटन के संभावित आकर्षक क्षेत्र के साथ-साथ अमीर व्यापारियों के लिए हाइपरसोनिक पॉइंट-टू-पॉइंट उड़ान में चीन की एक बड़ी सफलता होगी। इस परियोजना को चीनी में बड़े निवेशकों का पूरा समर्थन हासिल है।

चीन बोला- पाकिस्तान के सियासी संकट से सीपीईसी परियोजना नहीं होगी प्रभावित

बीजिंग (ईएमएस)। चीन ने अभिन्न दोस्त पाकिस्तान के साथ अपने प्रगाढ़ संबंधों को लेकर कहा कि इस्लामाबाद में बढ़ते राजनीतिक संकट से सदाबहार सहयोगी के साथ 60 अरब डॉलर वाली सीपीईसी परियोजनाओं पर समग्र सहयोग प्रभावित नहीं होगा। सतर्क रुख रखते हुए चीन पाकिस्तान में हाल में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिकी साजिश होने के आरोपों पर संसद को भंग कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने संसद को भंग करने और नए चुनावों की घोषणा की वैधता पर फैसला के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

पाकिस्तान में राजनीतिक और संवैधानिक संकट पर प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजनीतिक स्थिति इस्लामाबाद के साथ बीजिंग के करीबी संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती है। साथ ही, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी दल देश का विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एकजुट रहेंगे।

उन्होंने कहा, 'चीन हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत का पालन करता है।' लिजियान ने कहा, 'चीन और पाकिस्तान सदाबहार रणनीतिक साझेदार हैं। इतिहास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य कैसा भी हो और घरेलू हालात बदल जाएं, चीन और पाकिस्तान के संबंध हमेशा अटूट और मजबूत रहेंगे।' उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि समग्र चीन-पाकिस्तान सहयोग और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) का निर्माण पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होगा।

पाकिस्तान के एक प्रगाढ़ मित्र के रूप में हम आशा करते हैं कि देश में सभी दल एकजुट रहेंगे और संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विकास और स्थिरता को बनाए रखेंगे। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग से जोड़ने वाले 60 अरब डॉलर के सीपीईसी के तहत चीन कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना सीपीईसी पर चीन के समक्ष विरोध जताया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरती है।

विपक्ष ने नारायण मूर्ति की बेटी की कर स्थिति पर सवाल उठाए

लंदन (ईएमएस)। ब्रिटेन के विपक्षी दल ने इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी और भारत में जन्मी अक्षता मूर्ति की गैर-निवासी कर स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनके पति ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है। गैर-निवासी स्थिति का मतलब है कि अक्षता मूर्ति विदेशों में अर्जित आय पर ब्रिटेन में कर का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। उनके पास इंफोसिस के शेयर हैं। यूके की निदेशक मूर्ति के प्रवक्ता ने कहा कि गैर-निवासी का दर्जा इसलिए है, क्योंकि भारत दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता नहीं देता है और वह ब्रिटेन में कानूनी रूप से सभी जरूरी कर का भुगतान करती हैं।

प्रवक्ता ने कहा, अक्षता मूर्ति भारत की नागरिक हैं, जो उनके जन्म का देश और माता-पिता का घर है।'' उन्होंने कहा, ''भारत अपने नागरिकों को एक साथ दूसरे देश की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, ब्रिटिश कानून के अनुसार मूर्ति को ब्रिटेन में कर उद्देश्यों के लिए गैर-निवासी माना जाता है। उन्होंने हमेशा अपने ब्रिटेन के पूरे करों का भुगतान किया है और करती रहेंगी।'' अक्षता मूर्ति की कर स्थिति का विवरण सबसे पहले बुधवार को द इंडिपेंडेंट अखबार में छपा। इससे ठीक पहले सुनक ने नए करों की घोषणा की थी, जो नए वित्त वर्ष के लिए लागू होंगे। विपक्षी लेबर पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उनका परिवार, जो इस समय 11 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है, गैर-निवासी के रूप में पंजीकृत होने जैसी कर कटौती योजनाओं से फायदा उठा रहा है।

50 साल से कम उम्र के सभी लोगों को मार डालो...

-बूचा में रूसी कमांडर ने दिए थे नरसंहार के आदेश

-नरसंहार का दोषी रूसी सैन्य कमांडर ओमुरबेकोव था

-ब्रिटिश मीडिया ने रूसी कमांडर को बूचा का कसाई कहा

कीव(ईएमएस)। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार का असली दोषी रूसी सैन्य कमांडर अजात्बेक ओमुरबेकोव था। जिसने रूसी सैनिकों को आदेश दिया था कि पचास से कम उम्र वाले पुरुषों की पहचान कर उन्हें मार दिया जाए और महिलाओं से गैंगरेप किया जाए। ये दावा ब्रिटिश मीडिया ने किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में रूसी कमांडर को बूचा का कसाई बताया है। रिपोर्ट की मानें, तो सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के कमांडर अजात्बेक ओमुरबेकोव ने नागरिकों की हत्या करने के बाद उनके परिजनों को शवों को दफनाने के लिए केवल 20 मिनट दिए थे। कहा जा रहा है ये सैन्य कमांडर ईश्वर में विश्वास रखता है और युद्ध से पहले उसने ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी से भी आशीर्वाद लिया था।

बूचा में शवों की जांच कर रहे अधिकारियों से रूसी हमलों में बचे शेष नागरिकों ने कहा कि रूसी सैनिकों ने यहां पहुंचाने के बाद नागरिकों से उनके दस्तावेज मांगे थे। इस दौरान उन्हें जहां भी ये लगा कि खतरा है, उन्होंने नागरिकों को गोली मार दी। नागरिकों के शरीर पर यूक्रेनी आर्मी के टैटू की तलाश में कई नागरिकों के जबरन कपड़े भी उतरवाए गए और महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस रूसी कमांडर को नरसंहार का दोषी बताया जा रहा है, उसे 2014 में रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री बुल्गाकोव ने बेहतरीन काम के लिए मिलिट्री मेडल से सम्मानित भी किया था। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, एक आर्मी कमांडर अपने सैनिकों की ओर से किए गए किसी भी वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार होता है।

प्लास्टिक वेस्ट को खत्म की दिशा में बढाया अहम कदम

-ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने खोजा नया तरीका

लंदन (ईएमएस)। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक वेस्ट खत्म की दिशा में अहम कदम बढाया। दुनिया भर के लिए मुसीबत बना प्लास्टिक वेस्ट ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने नया तरीका खोज लिया है। साइंटिस्टों ने प्लास्टिक के कचरे की वैश्विक समस्या के प्राकृतिक निदान की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। यहां कि यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की गई स्टडी में रिसर्चर्स ने एक विशेष एंजाइम का पता लगाया है, जो टीपीए यानी टेरेफ्थेलेट को तोड़ने में सक्षम है।

टीपीए का इस्तेमाल पीईटी यानी पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि पीईटी प्लास्टिक से एक बार उपयोग वाली पेय पदार्थ की बोतलें, कपड़े व कालीन आदि का निर्माण किया जाता है। इस स्टडी का नेतृत्व मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन डुबाइस और पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के प्रो. जॉन मैकगीहन ने किया। इन्होंने साल 2018 में एक अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था, जिसने पीईटी प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम एक प्राकृतिक एंजाइम का निर्माण किया था। प्रो. जॉन मैकगीहान के अनुसार, 'पिछले कुछ वर्षों में एंजाइम इंजीनियरिंग के जरिये पीईटी प्लास्टिक को बिल्डिंग ब्लाक्स के रूप में तोड़ने की दिशा में अविश्वसनीय प्रगति हुई है। इसके जरिये बिल्डिंग ब्लाक्स को सामान्य अणुओं में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया के जरिये प्लास्टिक कचरे को खाद के रूप में तब्दील कर दिया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि हमने डायमंड लाइट सोर्स पर शक्तिशाली एक्स-रे के इस्तेमाल से टीपीएडीओ एंजाइम का 3डी ढांचा तैयार किया, जिससे पता चला कि ये किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है।हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जिसका अधिकांश भाग लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, यह आशा की जाती है कि यह कार्य टीपीएडीओ जैसे जीवाणु एंजाइमों में सुधार के द्वार खोलेगा।

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वे हाल ही में गठित सुरक्षा गठबंधन 'ऑकस' के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर जारी चिंताओं के बीच यह घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑकस की प्रगति पर विचार करने के बाद इस योजना की घोषणा की। तीनों देशों ने यह गठबंधन बीते साल सितंबर में बनाया था।

नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक रोधी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पर एक नया त्रिपक्षीय सहयोग बनाने के साथ ही सूचना साझा करने की प्रक्रिया को विस्तार देने तथा रक्षा नवोन्मेष पर सहयोग को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका, रूस और चीन सभी का ध्यान हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास पर है। यह एक ऐसी तेज प्रणाली है, जिसे कोई भी मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली बीच में रोक नहीं सकती।

अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष जनरल मार्क मिली ने बीते साल अक्टूबर में इस बात की पुष्टि की थी कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। मिली ने एक साक्षात्कार में चीन के इस परीक्षण को बेहद अहम करार दिया था। साथ ही उन्होंने इस पर चिंता भी जताई थी। मॉरिसन ने कहा हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दो साल पहले जारी की गई रणनीतिक योजना के अनुरूप है।

अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में मलबा पृथ्वी की कक्षा में मौजूद

-यही हाल रहा तो मलबे से 'बेकार' हो जाएगा स्पेस

वॉशिंगटन (ईएमएस)। इंसान को अंतरिक्ष में पहला कदम रखे 50 साल से अधिक समय हो गया है। अब वैज्ञानिकों की नजर मंगल जैसे ग्रह पर है जो कभी एक सपना हुआ करता था। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को कई उल्कापिंड की आतिशबाजी दिखाई पड़ी थी। इस रहस्यमय रोशनी को लेकर खगोलविद जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि यह दरअसल चीनी रॉकेट का मलबा था जो पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश कर रहा था।

इसी तरह का मलबा बड़ी मात्रा में हमारी पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है। अक्सर इसी मलबे के टुकड़े धरती पर जलते हुए गिरते हैं जो कई बार रिहायशी इलाकों में गिरने पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मलबे को लेकर कई सवाल लोगों के जेहन में हैं, जैसे- अंतरिक्ष में मलबा कहां से इकट्ठा होता है, इस मलबे से क्या नुकसान है और क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट के मलबे ने जाम लगा दी है? 'खगोलीय मलबा' लॉन्च व्हीकल या स्पेसक्राफ्ट के टुकड़ों से मिलकर बना होता है जो धरती से सैकड़ों किमी ऊपर तैरता रहता है। मलबे के विशालकाय टुकड़ों का स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। अंतरिक्ष में विस्फोट से भी कचरा पैदा है या अक्सर देशों द्वारा किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण या अपनी ही सैटेलाइट को तबाह करने से भी मलबा बढ़ता है।

रूस, चीन, अमेरिका और भारत अपनी सैटेलाइट्स को खत्म करने वाले देश हैं जिनसे अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा होता है। यह मलबा इसलिए खतरनाक है कि क्योंकि यह 25,265 किमी/घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाता है। यह रफ्तार किसी भी बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए काफी है। एक्सपर्ट कहते हैं, 'हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट में प्रवेश करती है, उसके खगोलीय मलबा बनने की संभावना होती है।' एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के मलबे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सरकार के मुताबिक सॉफ्टबॉल से बड़े मलबे के लगभग 23,000 टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। 1 सेमी से बड़े मलबे के 5 लाख टुकड़े हैं और करीब 1 मिमी या उससे बड़े मलबे के 100 मिलियन टुकड़े ऑर्बिट में मौजूद हैं। आईएसएस के पास मौजूद मलबे के टुकड़े दिन में 15-16 बार धरती का चक्कर लगाते हैं जिससे टकराव का खतरा बढ़ जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) का अनुमान है कि पृथ्वी की कक्षा में सभी अंतरिक्ष पिंडों का कुल द्रव्यमान 9,600 टन से अधिक है। ईएसए के होल्गर क्रैग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'अगर इसी तरह मलबा बढ़ता रहा तो एक दिन अंतरिक्ष का एक क्षेत्र बेकार हो जाएगा।' नासा का कहना है कि कक्षा में 600 किमी से कम ऊंचाई पर मौजूद मलबा कुछ साल में धरती पर वापस गिरेगा। लेकिन 1000 किमी से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद कचरा करीब एक शताब्दी या उससे अधिक समय पर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा। मलबे के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं सैटेलाइट्स, जिनकी भीड़ पृथ्वी की कक्षा में बढ़ती जा रही है।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में कुल 4550 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसमें 3790 सैटेलाइट्स निचली कक्षा में मौजूद हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को विभिन्न देशों की 50 अलग-अलग ऑपरेटर्स या स्पेस एजेंसियां संचालित करती हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक सैटेलाइट्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की हैं (1655)। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय की 129, रूसी रक्षा मंत्रालय की 125, नासा की 60, इसरो की 47 और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की 45 सैटेलाइट ऑर्बिट में मौजूद हैं। देशवार देखें तो अमेरिका की सबसे अधिक-2804, चीन की 467, ब्रिटेन की 349, रूस की 168, जापान की 93 और भारत की 61 सैटेलाइट अंतरिक्ष ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं।

मालूम हो कि साल 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने अंतरिक्ष के 'कबाड़खाने' में तब्दील होने की चेतावनी दी। उनकी इस थ्योरी को 'केसलर सिन्ड्रोम' के नाम से जाना गया जिसके मुताबिक पृथ्वी की कक्षा में मौजूद कचरा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां यह और अधिक मात्रा में खगोलीय मलबा पैदा करेगा जो सक्रिय सैटेलाइट्स, ऐस्ट्रोनॉट्स और मिशन प्लानर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है।

विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ उनकी गुणवत्ता बरकरार रखना भी जरूरी:मुख्यमंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, तब यह आवश्यक है कि विकास कार्य न केवल समय पर पूरे हों बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहे। अहमदाबाद में गुजरात कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिवादन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यभर में सड़कों और मकानों का निर्माण विकास प्रक्रिया को निरंतर गतिशील रखने वाले कारक हैं। कुल मिलाकर देखें तो कंस्ट्रक्शन का तेज गति से कार्यरत होता है, तब राज्य सरकार ने भी गुणवत्तायुक्त कार्यों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की मुश्किल होती है, तो उसके निवारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। छोटे-बड़े अनेक व्यवसायों के साथ जुड़े लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्य किया जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमें 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र दिया है, जिसे चरितार्थ कर आज हम 'सबका प्रयास, सबका विश्वास' हासिल कर सके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को हम सभी साथ मिलकर साकार करेंगे। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों से कार्य की कीमत नहीं बल्कि गुणवत्तायुक्त कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास में निर्माण कार्य से जुड़े कांट्रेक्टरों का बड़ा योगदान है। गुजरात देश का विकास इंजन है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिविल इंजीनियर के तौर पर अपने कार्यकाल के संस्मरण ताजा किए।

सड़क एवं भवन मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर है। केंद्र और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सूत्र 'हर हाथ को काम, काम का सही दाम' को सार्थक कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य क्षेत्र में स्टील, सीमेंट, डामर और रेती जैसी चीजों की कीमत बढ़ने से निर्माण कार्यों में अनेक विसंगतियां पैदा हुई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अनेक करारों में बदलाव किया, जो निर्माण व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए हितकारी साबित होगा।

सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि शहर, राज्य और देश के विकास में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का बड़ा योगदान है। निर्माण कार्य क्षेत्र लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में भी अग्रसर है।

गुजरात कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदपटेल ने कहा कि निर्माण कार्य देश के विकास की धरोहर हैं। कोविड-19 के दौरान वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी सहित अनेक समस्याओं को लेकर राज्य सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के प्रति आभार व्यक्त किया।

विवादित बयान के बाद जीतु वाघाणी ने कहा –उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की दरकार नहीं

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्य के शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी के शिक्षा को लेकर बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच जीतु वाघाणी ने आज स्पष्टता करते हुए कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है और यह गुजरात को बदनाम करने की एक साजिश हैं गुजरात के गौरव के लिए मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं हैं बता दें कि बीते दिन शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जिन्हें गुजरात में शिक्षा अच्छी नहीं लगती है वह गुजरात छोड़कर वहां चले जाएं जहां उन्हें शिक्षा बेहतर लगती हैं दरअसल शिक्षा मंत्री कटाक्ष करते हुए यह बोल गए थे कि जिस राज्य की शिक्षा जिन लोगों को बेहतर लगती है, उन्हें उसी राज्य में चले जाना चाहिएं इस बयान के जरिए जीतु वाघाणी ने दिल्ली की शिक्षा नीति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर कड़े प्रहार किए थें जब बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया तो दी शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी ने आज कहा कि उन्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं हैं

विश्व बैंक 'गुजरात रेज़िलिएंस सिटी डेवलपमेंट' कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद को देगा 3 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण

- (अहमदाबाद) विश्व बैंक 'गुजरात रेज़िलिएंस सिटी डेवलपमेंट' कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद को देगा 3 हज़ार करोड़ रुपए का ऋणमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार तथा अहमदाबाद महानगर पालिका के बीच हुई बैठक

अहमदाबाद (ईएमएस) विश्व बैंक द्वारा अहमदाबाद महानगर को 'गुजरात रेज़िलिएंस सिटी डेवलपमेंट' कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण देने का सैद्धातंकि रूप से निश्चय किया गया है। विश्व बैंक द्वारा देश के विकसित शहरों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ढाँचागत सुविधाओं के विकास कार्य के लिए ऋण दिया जाता है। इसलिए विश्व बैंक द्वारा गुजरात के अहमदाबाद को पहली पसंद के रूप में ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में गुरुवार को इस संदर्भ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ शहरी विकास विभाग तथा अहमदाबाद महानगर पालिका के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहरी विकास राज्य मंत्री विनोद मोरडिया, विश्व बैंक की प्रतिनिधि सुश्री मेस्करीन बरहाने, रोलेंड व्हाइट, हर्ष गोयल तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी, प्रधान शहरी विकास सचिव मुकेश कुमार तथा अहमदाबाद महानगर पालिका आयुक्त लोचन सेहरा उपस्थित थे। रेज़िलिएंस सिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक द्वारा संबंधित महानगर पालिकाओं को सस्टेनेबल तथा समयानुकूल विकास कार्य भविष्य के दीर्घकालिक आयोजन के साथ शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस बैठक में अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा इससे संबंधित शुरू की गई अलग-अलग योजनाओं का रूपरेखा सहित प्रेज़ेंटेशन दिया गया। अहमदाबाद शहर की वर्ष 2050 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को शुरू किया गया है। विश्व बैंक द्वारा 3000 करोड़ रुपए का ऋण अहमदाबाद को आवंटित किया जाएगा। इसके अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं में वर्तमान एसटीपी की क्षमता में वृद्धि तथा तकनीकी अपग्रेडेशन, नए एसटीपी का निर्माण, इंडस्ट्रियल रियूज़ के लिए टेर्शयरी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, वर्तमान मुख्य ड्रैनेज लाइनों का पुनर्वास तथा नए माइक्रो टनलिंग लाइन के कार्य, खारीकट कैनाल डेवलपमेंट तथा तालाब डेवलपमेंट, उनका रखरखाव तथा स्टॉर्म वोटर ड्रैनेज लाइन के कार्य शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन कर्यों को शीध्र शुरू कर समय पर पूर्ण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। विश्व बैंक की टीम के प्रतिनिधिगण गुजरात के विकास तथा हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के अत्याधुनिक विकास से प्रभावित हुए। विश्व बैंक की यह टीम 13 अप्रैल तक अहमदाबाद में है। इस दौरान यह टीम महानगर पालिका की इन योजनाओं की रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर आगामी जुलाई-2022 तक ऋण संबंधी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर अहमदाबाद महानगर पालिका को यह ऋण देगी।

विश्व प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी में त्रिदिवसीय 'श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव' आज से

- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल परिक्रमा के प्रारंभ दिवस पर करेंगे आद्यशक्ति का दर्शन-अर्चन

- अंबाजी-गब्बर में लाइट एण्ड साउण्ड शो, सांस्कृतिक विलेज, अंबाजी मंदिर की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे

अहमदाबाद (ईएमएस) विश्व प्रसिद्ध यात्राधाम आद्यशक्ति पीठ अंबाजी में चैत्री नवरात्रि के पावन पर्व पर 8 से 10 अप्रैल के दौरान 'श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव' का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड तथा श्री आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट के उपक्रम से इस 'श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा' का आयोजन किया गया है। जूनागढ स्थित गिरनार की हरित परिक्रमा की परम्परा की भाँति अंबाजी में यह परिक्रमा आरंभ होने जा रही है। आद्यशक्ति धाम के दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब एक ही स्थान पर एक साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस परिक्रमा के प्रारंभ अवसर पर यानि 8 अप्रैल शुक्रवार को शाम अंबाजी धाम पहुँचेंगे और आद्यशक्ति अंबा का पूजन-अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर अंबाजी गब्बर में 13.35 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित लाइट एण्ड साउण्ड शो का लोकार्पण करेंगे। पटेल कोटेश्वर महादेव मंदिर में 3 करोड़ की लागत से होने वाले नवीनीकरण कार्यों तथा यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे। वे गब्बर स्थित सांस्कृतिक विलेज का उद्घाटन तथा अंबाजी मंदिर की अत्याधुनिक वेबसाइट और गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि त्रिदिवसीय श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव के अंतर्गत 8 अप्रैल को सुबह 6 से 7 बजे तक पुजारियों तथा संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी मंदिरों की मूर्तियों की प्रक्षालन विधि की जाएगी। इसके बाद सुबह 7 से 11 बजे तक शोभायात्रा/ज्योतयात्रा तथा परिक्रमा यात्रा आयोजित होगी। आदिवासी आश्रमशाला-अंबाजी की 51 बेटियों द्वारा गब्बर गेट सर्किल से गब्बर प्रवेश द्वार तक कलश यात्रा तथा धार्मिक उत्सव सेवा समिति द्वारा गब्बर की चोटी पर से माताजी की ज्योत लाकर सभी मंदिरों में ज्योत अर्पण कार्यक्रम के साथ परिक्रमा का प्रारंभ होगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अखिल भारतीय नागर परिषद् तथा समग्र गुजरात नागर परिषद् (महामंडल) द्वारा 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में स्थित कुल 5 यज्ञशालाओं में विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाएँगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बनासकाँठा ज़िले की विभिन्न मंडलियों द्वारा भजन/सत्संग कार्यक्रम आयोजित होंगे। सायं 6.30 बजे आरती के दौरान महाभिषेक कार्यक्रम आयोजित होगा। चैत्री नवरात्रि के पवित्र दिवसों में आयोजित इस श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा के दूसरे दिन यानि 9 अप्रैल को सुबह 9 से दूसरे दिन सुबह 9 बजे (24 घण्टों) तक अखिल ब्रह्मांड माँ बहुचर आनंद गरबा मंडल ट्रस्ट-अहमदाबाद के 646 मंडलों द्वारा आनंद गरबा की अखंड धुन की जाएगी। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी मंदिरों में ध्वजा अर्पण तथा परिक्रमा आयोजित होगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अखिल भारतीय नागर परिषद् तथा समग्र गुजरात नागर परिषद् (महामंडल) द्वारा 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में स्थित कुल 5 यज्ञशालाओं में विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाएँगे तथा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बनासकाँठा ज़िले की विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा भजन/सत्संग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी प्रकार 10 अप्रैल को सुबह 9 से अगले दिन सुबह 9 बजे (24 घण्टों) तक अखिल ब्रह्मांड माँ बहुचर आनंद गरबा मंडल ट्रस्ट-अहमदाबाद के विभिन्न मंडलों द्वारा आनंद गरबा की अखंड धुन का समापन कर श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में पालखी यात्रा आयोजित की जाएगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अखिल भारतीय नागर परिषद् तथा समग्र गुजरात नागर परिषद् (महामंडल) द्वारा 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग में स्थित कुल 5 यज्ञशालाओं में विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाएँगे, जिनमें संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी शामिल होंगे।

गुजरात में कोरोना के 8 नए मरीज, 9 ठीक होकर घर लौटे, रिकवरी रेट 99.10 प्रतिशत

अहमदाबाद (ईएमएस) गुरुवार को गुजरात में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए, वहीं 9 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गएं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 99.10 प्रतिशत हैं राज्य में फिलहाल कोरोना के 73 एक्टिव मामलों में 71 स्टेबल हैं और 2 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं जबकि 1212956 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10942 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी हैं पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 3, खेडा में 2, गांधीनगर कॉर्पोरेशन, कच्छ और वडोदरा में 1-1 समेत राज्यभर में केवल 8 कोरोना संक्रमित मरीज दर्ज हुए हैं जबकि 6 कॉर्पोरेशन और 30 जिलों में कोरोना का एक भी केस पिछले 24 घंटों में दर्ज हुआं 6 कॉर्पोरेशन में वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर शामिल हैं जबकि 30 जिलों में अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, अरवल्ली, बनासकांठा, भरुच, भावनगर, बोटाद, छोटाउदेपुर, दाहोद, डांग, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, महीसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी और वलसाड शामिल हैं दूसरी आज राज्यभर में 34437 लोगों का वैक्सीनेशन किया गयां जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 1294 को पहला और 15984 को कोरोना का दूसरा डोज दिया गयां 15 से 18 वर्षीय 314 किशोरों को पहली और 3100 को कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाई गईं 12 से 15 वर्षीय 6138 किशोरों को कोरोना का पहला टीका लगाया गयां जबकि 7607 लोगों को बूस्टर डोज दिया गयां राज्य में अब तक 106411060 लोगों का वैक्सीनेट किया जा चुका हैं

आरक्षण का लाभ लेने के बाद उम्मीदवार जनरल की खाली जगहों पर दावे नहीं कर सकेगा

अहमदाबाद, ७ अप्रैल।

गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सहायक लिपिक की नौकरी के लिए अनुसूचित जाति कैटेगरी के १२२ उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें यह उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी की रिक्त (खाली) जगहों के लिए अपनी उम्मीदवारी को ध्यान में लेने के लिए कोर्ट को अर्जी की थी। क्योंकि सामान्य क्षेणी में चयन हुए पिछले उम्मीदवारों की अपेक्षा उनका मेरिट ज्यादा था। जस्टिस बिरेन वैष्णव ने अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए योग्य बनने के लिए उम्र और अन्य मापदंडों से संबंधित छूट लिया है और इसी वजह से उनको सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए आरक्षण श्रेणी के मेरिट प्राप्त उम्मीदवार माने नहीं जा सकेंगे।

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सहायक क्लर्क की ७६७ जगहों की भर्ती के लिए घोषणा की थी। फरवरी २०२० में ५२५ उम्मीदवारों का चयन की सूची तैयार करने के बाद, १२१ सीटें रिक्त थी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में भी इतनी ही सीटें खाली थी। एससी श्रेणी के यह उम्मीदवारों ने खाली सीटों पर दोनों श्रेणी में अपना दावा किया था, उन्होंने साथ में ऐसी दलील पेश की कि आरक्षण श्रेणियों के लिए कट-ऑफ ६१ अंक था जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह कट ऑफ ५२ फीसदी था। फिर भी सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या नहीं थी और १२१ सीटें खाली रही थी। एसटी श्रेणी में सिर्फ पांच ही जगहों को भरा जा सका था।

जबकि यह अर्जीकर्ता एससी श्रेणी के उम्मीदवार थे जिन्होंने ५२ से ६१ फीसदी के बीच मार्क्स लिया था और सामान्य श्रेणी के चयन की सूची में स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे। उनकी यह मांग का हाईकोर्ट तरफ से प्रतिनिधित्व करते वकील ने विरोध किया था। वकील ने सरकारी परिपत्र को बताकर कहा था कि यदि आरक्षण कोटा के उम्मीदवारों को यह निश्चित श्रेणी के लिए मामूली पात्रता मानदंड कोई लाभ मिल गया हो तो वह/अपनी मेरिट वाले उम्मीदवार के तौर पर सामान्य श्रेणी की या अन्य श्रेणी की सीटों पर दावा नहीं कर सकेगा।

वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद पशु नियंत्रण बिल लाएगी सरकार : रणछोड देसाई

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात भाजपा के नेता रणछोड देसाई ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण और वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही पश नियंत्रण बिल लाने का आश्वासन दिया हैं बता दें कि राज्यभर में खासकर शहरों में आवारा पशुओं की वजहों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी हैं ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए गुजरात सरकार ने विधानसभा में पशु नियंत्रण विधेयक पेश किया थां विधानसभा में पशु नियंत्रण बिल पेश होने के बाद राज्यभर में पशुपालकों ने इसका कड़ा विरोध कियां विभिन्न समाजों ने भी पशु नियंत्रण बिल लाने से पहले आवारा पशुओं की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और पशुपालकों के साथ बैठक हुई थीं जिसमें उचित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पशु नियंत्रण विधेयक स्थगित रखने का मुख्यमंत्री आश्वासन दिया हैं गुजरात भाजपा के नेता रणछोड देसाई ने बताया कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और पशु पालकों की समस्याओं का समाधान होने के बाद ही मुख्यमंत्री ने पशु नियंत्रण विधेयक लाने का फैसला किया हैं उन्होंने कहा कि आगामी महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में जहां भी पशु पालक रहते हैं उनकी पहचान कर हाईकोर्ट निर्देशानुसार उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मुख्यमंत्री आश्वासन दिया हैं पशु पालक समाज की मांग है कि पहले पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और उसके बाद नया कानून लागू किया जाएं राज्य सरकार जो कानून बनाने जा रही है उसमें सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के पकड़े जाने पर उसके मालिक को एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हैं जो पशुपालकों की बड़ी मुश्किलें पैदा करेगां पशु पालकों ने सरकार से गौचर की जमीनें भी जल्द से जल्द खाली करवाने की मांग की थीं

जीतू वाघाणी के निवेदन पर प्रहार

आप की सरकार बनेगी तो शानदार शिक्षा दी जाएगी : मनीष सिसोदिया

२७ वर्ष से गुजरात में शासन करते भाजपा अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकने का आप के नेता ने किया दावा

अहमदाबाद, ७ अप्रैल।

जिनको गुजरात की शिक्षा पसंद नहीं हो यह सर्टिफिकेट लेकर जहां पसंद हो वहां जा सकता है यह शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने दिए निवेदन पर भाजपा घिरते हुए दिखाई दे रही है।

वाघाणी ने गत दिन राजकोट में अपने भाषण में यह बात कहने के बाद अब दिल्ली के डेप्युटी सीएम तथा शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, पिछले २७ वर्ष से गुजरात में शासन करते भाजपा अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सका। सिसोदिया ने तो जीतू वाघाणी को यहां तक बताया था कि लोगों को गुजरात छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में आप की सरकार बनेगी तो यहां भी दिल्ली जैसा शानदार शिक्षा दी जाएगी भापजा के स्थापना दिन के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए राजकोट पहुंचे जीतू वाघाणी दो मामले में आलोचना के शिकार हुए। पहले तो उन्होंने एक पत्रकार ने युवराजसिंह जाडेजा की गिरफ्तारी मामले में पूछने पर वाघाणी ने सामने सवाल किया था कि, युवराजसिंह जाडेजा कौन है यह मामले में जीतू वाघाणी सोशल मीडिया पर जैसे विशेष ट्रोल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसी बात की थी कि जो गुजरात में बढ़े हुए यहां कामधंधा किया है और फिर भी गुजरात की आलोचना करते हो ऐसे लोग अपने बच्चों के सर्टिफिकेट लेकर उनको जिस राज्य में अच्छा लगता हो वहां जा सकते है।

उन्होंने यह भी कहा था कि जिस जगह पर हम पले बढ़े है, हमारे बाबादादा ने जहां संपत्ति खड़ा किया उस जगह को हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन यदि हमें यह पसंद नहीं हो तो हमें जहां इच्छा हो वहां चले जाना चाहिए। अभी दो सप्ताह पहले दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी को गुजरात विरूद्ध दिल्ली की शिक्षा मॉडल पर चर्चा करने के लिए खुली चुनौती दी।

महिला को पूछे बिना ही हाईकोर्ट पहुंच गया

कोर्ट द्वारा शख्स को ५ हजार का जुर्माना लगाया गया

अहमदाबाद, ७ अप्रैल।

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा एक शख्स को ५००० रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह शख्स ने कोर्ट के समक्ष पेशकश की थी कि, इसकी प्रेमिका को परिवार के लोगों ने जबरदस्ती गायब कर दिया है क्योंकि वह उनके संबंध के विरोध में थे।

कोर्ट ने यह पेशकश पर कार्रवाई करने पर अमरेली शहर की पुलिस को जांच करने का आदेश दिया था। अमरेली पुलिस ने जानकारी दी कि, अर्जीकर्ता पड़ोस में रहती एक महिला के एक तरफा प्रेम में था। महिला गायब हुई होने का कारण भी पुलिस जांच में सामने आया। महिला अपनी इच्छा के युवक के साथ भाग गई थी और इसके साथ शादी कर ली। २२ जनवरी को वह अपने मां-पिता के घर पर वापस आई थी। अर्जीकर्ता को लगा कि महिला के परिजनों ने अपने से अलग करने के लिए महिला को कहीं भेज दिया है। युवक पहले तो पुलिस स्टेशन पहुंचा और बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने आरोप लगाया कि महिला की जान खतरे में है और इसके पिता और भाई ने इसे कहीं पर छिपाकर रखा है। यह गैरकानूनी प्रवृत्ति है। इसके अलावा इसने दावा किया था कि लापता हुई महिला और यह पिछले १५ वर्ष से रिलेशनशिप में है। यह आरोपों को सुनकर कोर्ट ने केस को गंभीरता से लिया और पुलिस को तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दिया था। जबकि जांच का परिणाम सामने आया तो यह चौंकाने वाला था। अर्जीकर्ता के वकील भी यह रिपोर्ट पढ़कर चौंक गये। पुलिस को जानकारी मिली की महिला अमरेली में एक निजी स्कूल में शिक्षक है। यह महाराष्ट्र के एक हिंदू व्यक्ति के साथ भाग गई थी और शादी कर ली थी। महिला का परिवार मुस्लिम होने की वजह से यह शादी को कबूल नहीं किया था और उन्होंने बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस का संपर्क नहीं किया। जबकि पुलिस अधिकारी ने महिला के साथ बातचीत की तो उसने बताया है कि वह अपने शादी जीवन में खुश है। यह परिवार के गुस्से के डर से घर पर वापस नहीं आई। महिला को जबकि अर्जीकर्ता बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि, मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। यह इसे विशेष जानती भी नहीं थी।

अहमदाबाद मंडल पर विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता रैली एवं प्रदर्शनी का आयोजन

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 को चिकित्सा विभाग द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के पर हेल्थ यूनिट कालूपुर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक जागरूकता रैली निकाली गई।तथा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एवं रेलवे फुट ओवर ब्रिज पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 500 से अधिक पैसेंजर एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोजलीन द्वारा कालूपुर हेल्थ यूनिट पर रोगियों को आजकल की लाइफ स्टाइल से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खान-पान तथा नियमित व्यायाम दैनिक जीवन में जरूरी बताया। इस अवसर पर 100 से अधिक स्टाफ, पेशेंट तथा सैनिटेशन स्टाफ ने भाग लिया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तथा मण्डल रेल प्रबंधक,कार्यालय सहित कई स्थानों पर स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी पोस्टर भी लगाए गये। कार्यक्रम के अंत में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक आलोक अग्रवाल ने सभी लोगों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे जोड़ेगी मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर शताब्दी एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच विस्टा डोम कोच यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा

अहमदाबाद ,सम्मानीय यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से पश्चिम रेलवे द्वारा 11 अप्रैल, 2022 से अस्थायी आधार पर ट्रेन संख्या 12009/10 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर केपिटल शताब्दी एक्सप्रेस में एक विस्टा डोम कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 12009/10 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर केपिटल शताब्दी एक्सप्रेस में 11.04.2022 से 10.05.2022 तक एक विस्टा डोम कोच जोड़ा जायेगा। विस्टाडोम कोच में कांच की बड़ी खिड़कियां, कांच की छतें, घूमने वाली सीटें और एक ऑब्जमर्वेशन लाउंज है, जिससे यात्री सुंदर बाहरी नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच में आरक्षण हेतु नई ट्रेन संख्या 02009/02010 लागू होगी अर्थात विस्टा डोम कोच की बुकिंग ट्रेन संख्या 02009/02010 के रूप में उपलब्ध होगी और 09 अप्रैल, 2022 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुलेगी। विस्टाडोम कोच में 44 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं

टाटा मोटर्स को वीआरएल लॉजिस्टिक्सम लिमिटेड से 1300 वाणिज्यिक वाहनों का ठेका मिला

मुंबई, 7 अप्रैल, 2022: भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक वाहन निर्माता टाटा मोटर्स को भारत में सरफेस लॉजिस्टिक्सम के अग्रणी वीआरएल लॉजिस्टिक्सि लिमिटेड से 1300 वाणिज्यिक वाहनों का ठेका (ऑर्डर) मिला है। इससे देश में वीआरएल के लॉजिस्टिक्सए वाले वाणिज्यिक वाहनों के बेड़े का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। इस ठेके में टाटा मोटर्स के मध्याम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन और इंटरमीडियेट तथा हल्के वाणिज्यिक वाहनों की श्रृंखला शामिल है, जो भारत में कंपनी के लॉजिस्टिक्स। परिचालन के लिये उपयुक्तम है। इन वाहनों का चयन ड्राइविंग की उन्न्त योग्यढता, ईंधन बचाने की उच्चट क्षमता और स्वानमित्वा के कम कुल खर्च के आधार पर हुआ है, जिससे वीआरएल लॉजिस्टिक्स् लिमिटेड अपने बेड़े की क्षमता बढ़ा सकेगी।

इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए, टाटा मोटर्स की वाणिज्यिक वाहन व्य वसाय इकाई में बिक्री एवं विपणन के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश कौल ने कहा, ''हम वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से 1300 वाहनों का सम्मा्नजनक ऑर्डर मिलने पर बहुत खुश हैं। मुझे विश्वांस है कि हमारे वाहन उनके परिचालन में बड़ा महत्वड लेकर आएंगे। टाटा मोटर्स में हम स्वोमित्वै की सबसे कम कुल लागत की पेशकश करने के लिये अपने वाहनों को बनाने का प्रयास करते हैं और हमारा सबसे व्यापक सर्विस नेटवर्क देश के सभी कोनों में उद्योग का सर्वश्रेष्ठन सर्विस सपोर्ट सुनिश्चित करेगा। हमें वीआरएल लॉजिस्टिक्स् लिमिटेड के साथ एक फायदेमंद भागीदारी की आशा है और हम उनके सुगम परिचालन के लिये सर्वश्रेष्ठस सहयोग की पेशकश करेंगे।''

राजकोट डिविजन के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री आर सी मीणा ने शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर जीता खिताब

राजकोट रेलवे डिविजन के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सीनियर डीओएम) श्री आर सी मीणा ने शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतकर राजकोट डिविजन का नाम रोशन किया है।

अधिक जानकारी देते हुए राजकोट डिविजन के सीनियर डीसीएम श्री अभिनव जेफ ने बताया कि महाराष्ट्र पुणे में हाल ही में आयोजित 55वें अखिल भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल शूटिंग केटेगरी में सटीक निशाना लगाते हुए श्री आर सी मीणा ने रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीता है। गौर तलब है कि श्री आर सी मीणा इससे पहले भी 54वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप मे 2019-20 में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग केटेगरी मे ब्रोंज मेडल जीत कर पश्चिम रेलवे का गौरव बढ़ा चुके है। श्री मीणा 2017 एवं 2019 में आयोजित राष्ट्रिय शूटिंग चैम्पियनशिप में भी गुजरात का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं।

इस शानदार सफलता के लिए राजकोट मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कुमार जैन ने श्री आर सी मीणा को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

अहमदाबाद में रामजी मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में भूपेंद्र पटेल की भावमय उपस्थिति

- मन की स्वच्छता के लिए आध्यात्मिक अनुभूति अनिवार्य: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद , मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जिस तरह शरीर से बीमारी को दूर करने के लिए स्वच्छता आवश्यक है, उसी तरह मन की स्वच्छता के लिए आध्यात्मिक अनुभूति भी उतनी ही अनिवार्य है। संतों और महात्माओं के मुख से परमात्मा के भजन सुनने से हम सभी को वह अनुभूति होती है। गुरुवार को अहमदाबाद में रामजी मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में संतों व महात्माओं से प्राप्त ज्ञान हम सभी को परमात्मा के समीप ले जाता है। भूपेंद्र पटेल ने विख्यात कथाकार पूज्य रमेशभाई ओझा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बाद में पूज्य रमेशभाई ओझा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का काठियावाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परमात्मा से प्रार्थना की कि संत-महात्मा अपनी मधुर वाणी से हम सभी को आशीष देते रहें और आने वाली पीढ़ी नई उपलब्धियां हासिल करे। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, मंत्री जगदीश पंचाल सहित कई विधायक मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे

विभिन्न निर्माण कार्य

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II, पश्चिम रेलवे, इंदौर रेलवे स्टेशन के सामने, पटेल ब्रिज के पास, इंदौर (एमपी) – 452001, निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते हैं : ई-निविदा सूचना क्र. : आईएनडी/डीआईएनएल/डिवाई.सीई/सी/II/99, दिनांक : 07.04.2022, दो लिफाफा प्रणाली. कार्य का नाम : पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में दाहोद – इंदौर, नई बीजी लाइन परियोजना के संबंध में गुनावाड (रहित) – धार (सहित) अनुभाग (14.02 किमी.) के बीच रेल्स की वेल्डिंग, पी वे सामग्री का परिवहन, अनुभाग/याड्र्स में मेन लाइन, लूप लाइन्स और प्वाइंट्स और क्रॉसिंग इत्यादि हेतु बीजी ट्रैक जोड़ना और बिछाना, मशीन क्रश्ड स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति और बिखराव, रिटेनिंग /बाउंड्री /टो दीवार का निर्माण, स्टील गर्डर कम्पोनेंट की कार्टिंग, रेलवे डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार ब्रिज कार्य (बड़े /छोटे – फाउंडेशन, सब-स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर) का निर्माण, याड्र्स, ब्रिज अप्रोचेस इत्यादि सहित फॉर्मेशन में कटिंग/एम्बैकमेंट में ब्लैंकेटिंग तथा जमीनी कार्य एवं अन्य आकस्मिक विविध कार्य इत्यादि. कार्य की अनुमानित लागत : ₹ 111,85,07,555.28. ईएमडी : ₹ 57,42,500/-, बोली जमा करने और खुलने की तिथि एवं समय : जमा करना : 03.05.2022 को 15.00 बजे तक. तकनीकी बोली खुलने की तिथि एवं समय : 03.05.2022 को 15.30 बजे. वेबसाइट विवरण, सूचना फलक स्थान जहां निविदा के सम्पूर्ण विवरण देखे जा सकते हैं तथा कार्यालय का पता : www.ireps.gov.in और उपरोक्त कार्यालय पता. 0007

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादक: लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95